जून-जुलाई, 2026, वर्ष-34, अंक-13

उत्तर प्रदेश संदेश

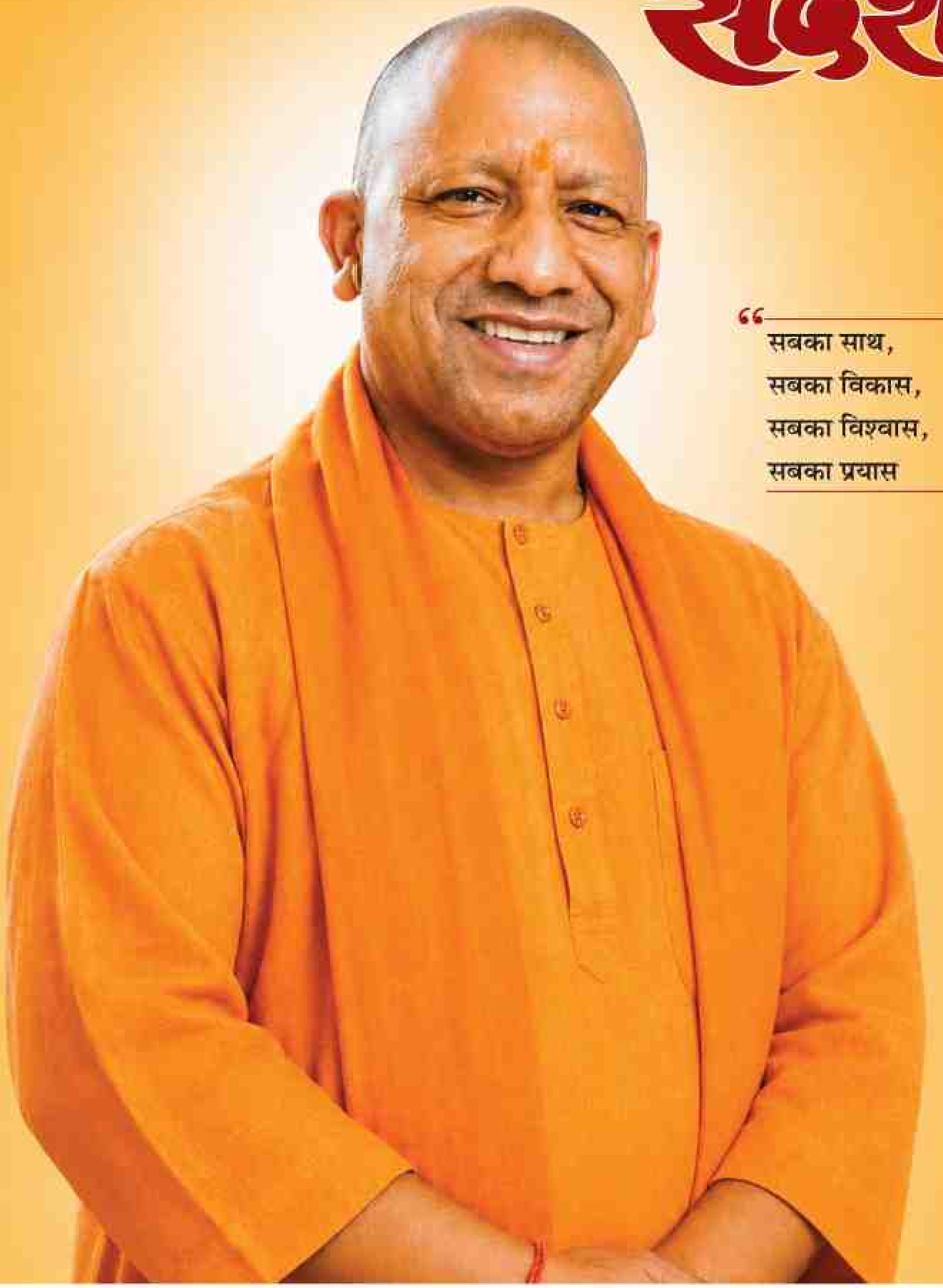

"सबका साथ,
सबका विकास,
सबका विश्वास,
सबका प्रयास"

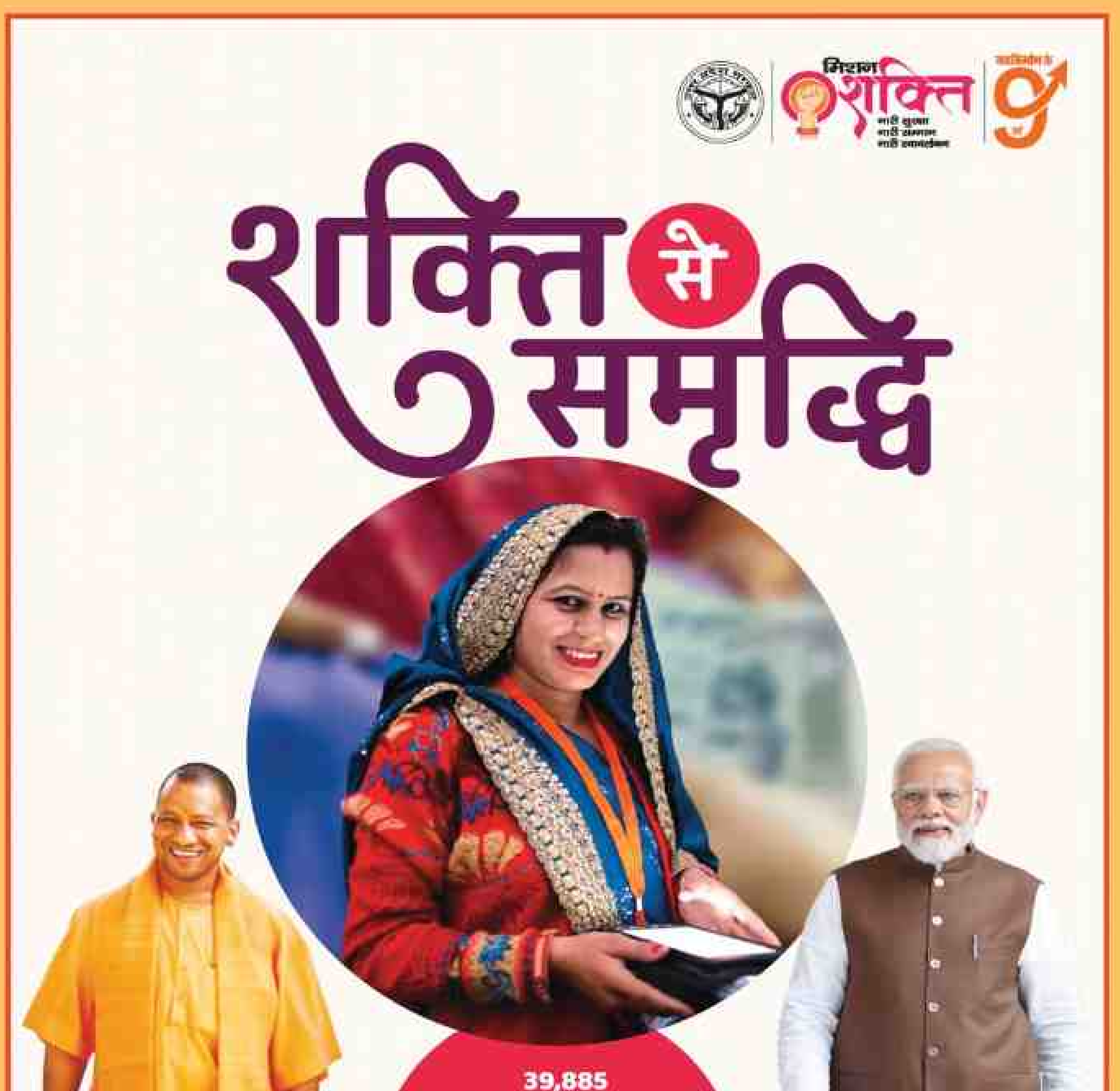

मिशन शक्ति
शक्ति से समृद्धि
39,885
बीसी सखियां सक्रिय,
50,000+ प्रशिक्षित
₹42,700 करोड़+
के वित्तीय लेनदेन
का रिकॉर्ड
आधी आबादी को पूरा अधिकार-डबल इंजन सरकार

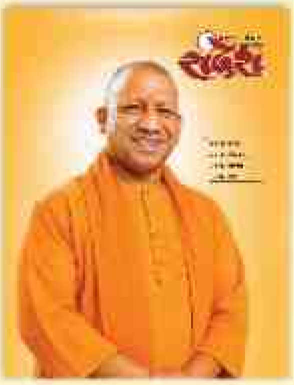

उत्तर प्रदेश
संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :
संजय प्रसाद
अपर मुख्य सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
विशाल सिंह
सूचना निदेशक

सम्पादकीय परामर्श :
अरविन्द कुमार मिश्र
अपर निदेशक, सूचना

चन्द्र विजय वर्मा
सहायक निदेशक (प्रकाशन)

दिनेश कुमार गुप्ता
उपसम्पादक, सूचना

अजय कुमार द्विवेदी
सहयुक्त संपादक

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ
ईमेल : upsandesh20@gmail.com
दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522-2239132-33, 9412674759, 7705800978

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं है। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

- राष्ट्रीय स्मृति का अटूट हिस्सा — 3
  -नरेंद्र मोदी
- पौधरोपण महायज्ञ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव — 6
  -योगी आदित्यनाथ
- प्रकृति, पर्यटन और सरकार — 9
  -डॉ. सौरभ मालवीय
- डबल इंजन सरकार में निरंतर विकसित होता यूपी — 13
  -सियाराम पांडेय 'शांत'
- ऑपरेशन कायाकल्प और पारदर्शी भर्तियां — 19
  -देवराज सिंह
- विकास की ओर बढ़ता दंगामुक्त उत्तर प्रदेश — 21
  -प्रमिला
- विदेश की राह छोड़ी, लौटे अपने गांव — 25
  -वीरेन्द्र पाठक
- विकसित भारत की यात्रा — 28
  -पूजा गुप्ता
- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना : संरक्षण से सशक्तीकरण तक — 32
  -डॉ. शिवानी कटारा
- प्रोजेक्ट गंगा से डिजिटली मजबूत होते गांव — 36
  -प्रदीप कुमार गुप्ता
- विकास की उड़ान भरता गोरखपुर — 42
  -रुद्रेश घिल्डियाल
- विकास के केंद्र में बुद्ध की क्रीड़ास्थली — 46
  -रवि प्रकाश
- जेवर से वैश्विक उड़ान, बदलते यूपी की पहचान — 49
  -अशोक सिंह
- प्राथमिकता पर प्राथमिक शिक्षा — 53
  -रजनीश वैश्य
- सबको शिक्षा, सबको छात्रवृत्ति — 58
  -डॉ. सोनाली शुभम
- उत्तम प्रयास, सर्वोत्तम आपूर्ति — 61
  -डॉ. सुयश नारायण मिश्रा

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश निरंतर विकसित हो रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में मौजूदा सरकार की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। बिना थके, बिना रुके सरकार ने राज्य के विकास रथ को आगे ही बढ़ाया है। आलस्य और प्रमाद को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की भावना पर हावी नहीं होने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में कल-कारखानों का ऐसा तंत्र विकसित करना चाहते हैं जिससे यहां के युवकों को रोजी-रोजगार के लिए अपना घर-बार छोड़कर देश के दूसरे राज्यों और शहरों की यात्रा न करनी पड़े। उन्हें विदेश न जाना पड़े। उनका सपना तो यह है कि विदेशी नागरिक भी उत्तरप्रदेश में खासकर पूर्वांचल में चाकरी करें। यह एक सकारात्मक सोच है और स्वागतव्य है। जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान सेवा आरंभ हो गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह दावा भी सच हो गया है कि अब चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने न केवल लखनऊ तक की हवाई यात्रा की, बल्कि इस बात के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई भी दी कि उन्होंने उन्हें चप्पल में हवाई जहाज की यात्रा का सुख प्रदान किया। यह प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुविधाएं अब अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गई हैं बल्कि उनकी पहुंच अब जनसामान्य तक हो गई है। प्रदेश में जिस तरह हर आम और खास की आय बढ़ी है, यह अपने आप में बेहद संतोषप्रद स्थिति है। शहर और गांव का समवेत विकास यह बताता है कि सरकार विकास के किसी भी मोर्चे की अनदेखी के पक्ष में नहीं है। योग सप्ताह के अवसर पर सरकार ने हर अमृत सरोवर पर योग सप्ताह का आयोजन किया। वहां विषय विशेषज्ञों ने तो योग को महत्ता बताई ही, क्षेत्रीय हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस अंक में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यादों पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलेख 'राष्ट्रीय स्मृति का अटूट हिस्सा' व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पर्यावरण संकेंद्रित आलेख 'पौधरोपण महायज्ञ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव' विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संरक्षण पर आधारित लेख प्रकृति, पर्यटन और योगी, योगी सरकार में किस्मत बदल गई यूपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश के विस्तार विकास पर आधारित आलेख तो है ही, विकास की उड़ान जैसे लेख भी हैं जो सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की अवधारणा को बल प्रदान करते हैं। यह अंक आपको कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें सतत इंतजार रहेगा।

सम्पादक

राष्ट्रीय स्मृति का अटूट हिस्सा

–नरेंद्र मोदी

छह जुलाई का दिन राष्ट्रवाद और निःस्वार्थ सेवा के आदर्शों में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए बहुत ही विशेष है। हम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म–जयंती मना रहे हैं। उनका जीवन साहस और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। उनके व्यक्तित्व में विद्वता, जनसेवा और उच्च नैतिक मूल्यों का अद्भुत संगम था। आधुनिक भारत के कुछ ही नेताओं में इतने सारे गुण एक साथ देखने को मिलते हैं।

उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था, जहां उन्हें सुख–सुविधाओं से भरपूर जीवन आसानी से मिल सकता था। उनके पिता सा आशुतोष मुखर्जी की गिनती अपने समय के महान शिक्षाविदों में होती थी, लेकिन तमाम सुविधाओं के बावजूद उन्होंने त्याग और राष्ट्रसेवा का मार्ग चुना। उनका दृढ़ विश्वास था कि चाहे अंग्रेजी शासन का विरोध हो, सांप्रदायिकता से लड़ाई हो या मानवीय संकटों का सामना, वे अपने समय की चुनौतियों के सामने मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते। इस सफर में उन्हें कई गहरे व्यक्तिगत दुख भी झेलने पड़े। पहले उन्होंने अपने छोटे बच्चे को खोया, फिर पत्नी का भी निधन हो गया। लेकिन उन्होंने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनका संकल्प और सशक्त हुआ, राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण और गहरा होता गया। उनके जीवन का सबसे बड़े उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू–कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। जेल और नजरबंदी भी उन्हें रास्ते में डिगा नहीं सकी। जब नजरबंदी के दौरान उनका निधन हुआ, तब वे उन अनगिनत लोगों से बहुत दूर थे, जिनके लिए जीवनभर संघर्ष करते रहे। इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं, जब किसी व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान देश की स्मृति का हिस्सा बन जाता है। डॉ. मुखर्जी का बलिदान भी ऐसा ही था। दशकों बाद, साल 2019 में आर्टिकल 370 और 35(ए) को हटाया जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी।

डॉ. मुखर्जी ने हमेशा राष्ट्रहित और भारतीय

मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने मजबूत संस्थानों का निर्माण किया और ऐसी व्यवस्थाएं बनाईं, जो उस समय की सोच से काफी आगे थीं। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए, तो राष्ट्रहित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप थे। शिक्षाविदों के एक सम्मेलन में डॉ. मुखर्जी ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों को केवल बाबू या कम वेतन वाले कर्मचारी तैयार करने की फैक्टरी समझना गलत है। हमें विद्यार्थियों को ऐसे तैयार करना होगा, ताकि वे नेतृत्व की भूमिका निभा सकें। इसके साथ ही वे वित्त, व्यापार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकें।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने नेतृत्व में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इनमें लाइब्रेरी की सुविधाओं में सुधार, विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक वस्तुओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और कृषि से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करना शामिल था।

बाद के वर्षों में इस भावना का एक और उदाहरण तब देखने को मिला, जब उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाने का निर्णय लिया। उस समय देश में कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था। उन्होंने महसूस किया कि देश को एक ऐसे नए विकल्प की जरूरत है, जो भारत की प्रगति की बात भी करे और सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा रहे।

डॉ. मुखर्जी का भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्यकाल बेहद अहम रहा। वे उद्योग को नए-नए आजाद हुए भारत के लोगों में सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास का संचार करने का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और मजबूत औद्योगिक नीति जैसी ऐतिहासिक पहल की और आधुनिक औद्योगिक भारत की नींव रखी। साथ ही वे हथकरघा, कुटीर उद्योग, कारीगरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिकों के हितों के भी प्रबल समर्थक थे।

आत्मनिर्भर भारत के स्पष्ट विजन के साथ जिस सिंदरी संयंत्र की स्थापना के लिए डॉ. मुखर्जी ने अथक प्रयास किए थे, उसकी कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने घोर उपेक्षा की। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार को उसके पुनरुद्धार का सौभाग्य मिला। उस कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे सार्वजनिक जीवन के अविस्मरणीय क्षणों में से एक बन गया।

आत्मनिर्भर भारत के स्पष्ट विजन के साथ जिस सिंदरी संयंत्र की स्थापना के लिए डॉ. मुखर्जी ने अथक प्रयास किए थे, उसकी कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने घोर उपेक्षा की। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार को उसके पुनरुद्धार का सौभाग्य मिला। उस कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे सार्वजनिक जीवन के अविस्मरणीय क्षणों में से एक बन गया।

डॉ. मुखर्जी ने पंडित नेहरू के

मंत्रिमंडल में शामिल होना इसलिए स्वीकार किया, क्योंकि वे मानते थे कि देश की आजादी के शुरुआती वर्षों में राष्ट्र निर्माण का दायित्व राजनीतिक मतभेदों से कहीं ऊपर है। उन्होंने पूरी निष्ठा और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि राष्ट्रीय महत्व के कुछ प्रश्नों पर देशहित में अलग मार्ग अपनाना आवश्यक है, तो उन्होंने पूरी गरिमा के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 75 वर्ष पहले पंडित नेहरू पहला संविधान संशोधन लेकर आए। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार माना गया। तब डॉ. मुखर्जी इसके सबसे मुखर आलोचक रहे थे। वे भली-भांति समझ चुके थे कि कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। समय के साथ उनकी यह आशंका सही साबित हुई। जो पार्टी 75 वर्ष पहले पहला संविधान संशोधन लेकर आई थी, उसी ने 1975 में देश पर आपातकाल थोपा। यही नहीं, 50 वर्ष पहले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाकर एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद पर कुठाराघात किया गया। वर्ष 1973 में जब बंगाल भीषण अकाल की त्रासदी से जूझ रहा था, तब उन्होंने पीड़ितों की सेवा में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि लोगों को भोजन मिल सके, जिसके लिए कई कैंटीन और रिलीफ सेंटर शुरू किए गए। उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए पंचाशेर मन्वंतर नाम की एक किताब भी लिखी। 1942 में जब मेदिनीपुर में भीषण चक्रवात आया, तब उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का नेतृत्व किया।

आज हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम प्रतिदिन उस भारत के निर्माण की दिशा में प्रयास करें, जिसकी उन्होंने परिकल्पना की थी। एक ऐसा भारत, जो सशक्त हो, एकजुट हो, आत्मविश्वास से भरपूर और संवेदनशील हो। देश के युवाओं पर मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बढ़-चढ़कर भागीदारी करेंगे और इस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएंगे। ◆

लेखक : भारत के प्रधानमंत्री हैं।

साभार : अमर उजाला (6 जुलाई, 2026)

पौधरोपण महायज्ञ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव

—योगी आदित्यनाथ

मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे अवसर विरले ही आते हैं, जब परंपरा और भविष्य एक ही दिशा में खड़े दिखाई देते हैं। आज पर्यावरण संरक्षण ऐसा ही एक विषय है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, जल संकट और जैव विविधता का क्षरण पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बनकर उपस्थित हैं। विज्ञान इनके समाधान खोज रहा है। नीतियां बन रही हैं। वैश्विक मंचों पर संकल्प लिए जा रहे हैं लेकिन भारत के लिए यह विमर्श नया नहीं है। हमारी सभ्यता ने हजारों वर्ष पूर्व प्रकृति और मानव के संबंध को जिस गहराई से समझा, वही आज विश्व के लिए समाधान का आधार बनता दिखाई दे रहा है।

अथर्ववेद का उद्घोष है, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह भाव केवल काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं, अपितु जीवन की संपूर्ण व्यवस्था का आधार है। ईशावास्योपनिषद हमें संयमित उपभोग का संदेश देता है। श्रीमद्भगवद्गीता लोकसंग्रह की बात करती है। भारतीय परंपरा में पंचमहाभूतों की अवधारणा बताती है कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व परस्पर जुड़ा हुआ है।

पीपल, वट, नीम, तुलसी, आंवला और अशोक हमारे सामाजिक जीवन में श्रद्धा के प्रतीक इसलिए बने क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रकृति का संरक्षण कानूनों से अधिक संस्कारों से होता है। आज विश्व जिस हरित विकास की चर्चा कर रहा है, उसका मूल तत्व भारतीय चिंतन में सदियों से है। अंतर केवल इतना है कि तब यह जीवनशैली थी, आज वैश्विक आवश्यकता बन चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी सांस्कृतिक चेतना को आधुनिक विकास दृष्टि के साथ जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी का राष्ट्रीय अभियान बनाया है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) एक वैश्विक जनांदोलन है, जो प्रकृति के लिए, प्रकृति के द्वारा के मंत्र के साथ प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह संदेश देता है कि जलवायु परिवर्तन का समाधान केवल सरकारों के निर्णयों से नहीं, नागरिकों के आचरण से भी निकलेगा। ग्लासगो में प्रस्तुत 'पंचामृत' का संकल्प भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक पेड़ मां के नाम अभियान भारतीय जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह अभियान मातृत्व के सम्मान को प्रकृति संरक्षण से जोड़ता है।

वर्ष 2017 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में 242

करोड़ से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में वन एवं वृक्षावरण की वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक प्रयासों से नहीं मिली है। इसके पीछे करोड़ों नागरिकों की सक्रिय सहभागिता है। इस वर्ष 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाये जा चुके हैं। इससे पूर्व विश्व पर्यावरण दिवस पर पांच करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।

पौधरोपण अभियान की विशेषता केवल आकार नहीं है। ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकाय तक माइक्रोप्लान तैयार किए गए हैं। लाखों सरकारी कार्मिक, जनप्रतिनिधि, किसान, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्थाएं, महिला समूह और सामाजिक संगठन इस महायज्ञ के सहभागी हैं। यह उस भारत की तस्वीर है जहां सरकार दिशा देती है और समाज उसे अपनी शक्ति में बदल देता है।

हमारा उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं है। उनका संरक्षण, संवर्धन और वृक्ष के रूप में विकास ही असली सफलता है। इसी दृष्टि से प्रदेश में पौधशालाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। स्थानीय जलवायु और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप फलदार, औषधीय, पर्यावरणीय, औद्योगिक तथा छायादार प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मिशन छाया, समृद्धि वन, समरस वन, अविरल धारा वन और हर खेत में मेड़, हर मेड़ पर पेड़ जैसे प्रयास वृक्षारोपण को समाज, कृषि, जल संरक्षण व जैव विविधता से जोड़ती हैं।

पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह भाव केवल काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं, अपितु जीवन की संपूर्ण व्यवस्था का आधार है। ईशावास्योपनिषद हमें संयमित उपभोग का संदेश देता है। श्रीमद्भगवद्गीता लोकसंग्रह की बात करती है। भारतीय परंपरा में पंचमहाभूतों की अवधारणा बताती है कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व परस्पर जुड़ा हुआ है।

उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 15 फीसदी और वर्ष 2047 तक 20 फीसदी हरित आवरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके पीछे जल संरक्षण, स्वच्छ वायु, उर्वर भूमि, जैव विविधता, कार्बन अवशोषण और भावी पीढ़ियों के स्वस्थ जीवन की व्यापक दृष्टि निहित है। विकसित उत्तर प्रदेश की कल्पना हरित उत्तर प्रदेश के बिना संभव नहीं है।

ऊर्जा, परिवहन, उद्योग और नागरिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हरित परिवर्तन आवश्यक है। इसी विचार के अनुरूप उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में लगभग साढ़े छह लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे लगभग 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को नई गति दे रही है। बायो ऊर्जा नीति कृषि अवशेषों और जैव अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना रही है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति भविष्य की ऊर्जा संरचना को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह केवल नई तकनीक को अपनाने का प्रयास नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की ऊर्जा सुरक्षा का आधार है।

स्वच्छ परिवहन भी इसी परिवर्तन का महत्वपूर्ण आयाम है। प्रदेश में 15.50 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों

का पंजीकरण हो चुका है। लगभग 2500 चार्जिंग स्टेशन हैं। इन्हें बढ़ाकर 10 हजार तक करने की दिशा में काम हो रहा है। तीव्र गति से विकसित हो रहे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे, एयरपोर्ट और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी समानांतर रूप से जारी है। ऐसे उपक्रमों में कई बार वृक्षों की कटान अपरिहार्य हो जाती है लेकिन विकास और प्रकृति के बीच संतुलन ही सुशासन की वास्तविक कसौटी है। इसी दृष्टि से हर परियोजना के साथ व्यापक वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी गई है।

प्रदेश ने 900 से अधिक विरासत वृक्षों का संरक्षण सुनिश्चित कर स्पष्ट किया है कि विकास अपनी प्राकृतिक धरोहर से विमुख होकर नहीं, बल्कि उसके सम्मान और संरक्षण के साथ आगे बढ़ता है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति

का संरक्षण केवल पर्यावरणीय दायित्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव है। हम पृथ्वी को माता, नदियों को जीवनदायिनी और वृक्षों को प्राणवायु का आधार मानते हैं। यही कारण है कि वृक्षारोपण हमारे लिए औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, जिसने हमें जीवन, अन्न, जल और ऊर्जा प्रदान की है। 12 जुलाई का वृक्षारोपण महायज्ञ इसी कृतज्ञता का विराट उत्सव है।

आइए, हम सभी इस महायज्ञ के सहभागी बनें। एक पौधा रोपें, उसे जीवित रखें और उसे भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाएं। यही हमारी संस्कृति का संदेश है, यही प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता है और यही विकसित भारत तथा विकसित उत्तर प्रदेश की हरित आधारशिला भी है। ◆

साभार : अमर उजाला (12 जुलाई, 2026)

लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

प्रकृति, पर्यटन और सरकार
सतत विकास की दिशा में प्रयास

—डॉ. सौरभ मालवीय

उत्तर प्रदेश प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध राज्य है। इसलिए यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं, इसलिए वह इसे प्रोत्साहित करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। उनके अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप विगत कुछ वर्षों में प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय में एक पंथ दो काज किए हैं अर्थात उन्होंने पर्यटन को प्रोत्साहित करके एक ओर राजस्व में वृद्धि करने का कार्य किया है, तो दूसरी ओर इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया है।

योगी सरकार ने प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को विश्व के समक्ष लाने के लिए अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए हैं।

पक्षी अभयारण्य में एआर–वीआर डोम की सुविधा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक एआर–वीआर डोम की सुविधा शीघ्र उपलब्ध की जाएगी। उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा यहां कई पर्यटन सुविधाओं का तेजी से विकास कराया जा रहा है। इन पर लगभग 2.81 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार राज्य के ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन पर पहली बार आगंतुकों को जंगल का वर्चुअल अनुभव प्राप्त होगा। लखनऊ से लगभग 43 किलोमीटर दूर कानपुर हाईवे स्थित शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य प्रमुख रामसर

साइट है। पक्षी प्रेमियों, प्रकृति को निकट से अनुभव करने वालों और शहरी भागदौड़ से दूर शांत वातावरण की खोज में जुटे पर्यटकों के लिए यह एक प्रमुख आकर्षण है। शांत, हरेभरे प्राकृतिक वातावरण में स्थित यह सेंचुरी सप्ताहांत पर्यटन के लिए बेहतरीन गंतव्य है। सर्दियों में यहां स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों की भारी आमद होती है। उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा यहां एआर–वीआर डोम के साथ–साथ कई अन्य सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है, जिनमें रिसेप्शन/टिकट/वेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, फूड एवं ओडीओपी कियोस्क, लैंडस्केपिंग एवं साइट डेवलपमेंट, पौधरोपण, बाहरी प्रकाश व्यवस्था, साइनेज आदि सम्मिलित हैं। एआर–वीआर डोम एक विशिष्ट प्रकार की अत्याधुनिक तकनीकी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि इसमें जंगल के किसी भी समय की सीन क्रिएट की जा सकती है। सुबह, देर शाम या रात के जंगल का दृश्य, जो अक्सर हम नहीं देख पाते हैं, वह हम इस अत्याधुनिक सुविधा के माध्यम से देख सकते हैं। डोम में बैठने के बाद आप चारों ओर का दृश्य देख सकते हैं। कई जगह तो ऊपर और नीचे का भी दृश्य दिखता है। इस पक्षी अभयारण्य में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाओं को साकार करने के लिए बोर्ड सक्रिय है। इसी क्रम में लखनऊ के विविध विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए क्यूरेटेड टूर कराए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से ईज माय ट्रिप के साथ एमओयू किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध राज्य है, जो बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। हमारा लक्ष्य है कि यहां आने वाले पर्यटक अद्वितीय और यादगार अनुभव लेकर लौटें। इसी दिशा में सुविधाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए रियायती टूर पैकेज

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली, रोमांच से भरे जंगल सफारी अनुभव और दुर्लभ वन्य जीवों की झलक को अब पर्यटक पहले से कहीं अधिक आसान और किफायती तरीके से देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने सैलानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक रात, दो दिन के पांच विशेष बजट पैकेज तैयार किए हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से तैयार टूर पैकेज पर्यटकों को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को करीब से अनुभव करने का मौका देगा। यह बजट पैकेज उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म, जंगल सफारी और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देगा। राजधानी लखनऊ के होटल गोमती से 15 दिसम्बर, 2025 से प्रारंभ होने वाले इस टूर पैकेज से संबंधित विशेष जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

लखनऊ–दुधवा यात्रा पैकेज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुविधा है। यात्रा पैकेज में पर्यटकों के ठहरने के लिए जंगल से मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर आरामदायक होटल की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रकृति का अनुभव और भी नजदीक से लिया जा सकेगा। यात्रा के दौरान स्वादिष्ट भोजन, प्रति यात्री दो पानी की बोतल, चाय की चुस्कियों के साथ अलाव का आनंद, अनुभवी गाइड और रोमांच से भरपूर जंगल सफारी भी पैकेज में सम्मिलित है।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के सचिव अमृत अभिजात का कहना है कि दुधवा नेशनल पार्क के लिए तैयार किए गए ये विशेष बजट राज्य में इको–टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को नई दिशा देंगे। निगम का उद्देश्य है कि पर्यटकों को सुरक्षित और किफायती यात्रा का अनुभव उपलब्ध कराया जाए, ताकि परिवार, विद्यार्थी और प्रकृति प्रेमी उत्तर प्रदेश की जैव विविधता को नजदीक से अनुभव कर सकें। दुधवा जैसे प्राकृतिक धरोहर स्थलों के माध्यम से स्थानीय रोजगार, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और सतत पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी।

आगरा के बटेश्वर में नाविक सुनाएंगे लोक कथाएं

यमुना तट पर बसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन ग्राम बटेश्वर में ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा देने का महत्वाकांक्षी प्रयास किया गया है। स्थानीय नाविकों को केवल नाव संचालन तक सीमित न रखते हुए उन्हें कहानी कहने की कला से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे

पर्यटकों को ब्राह बटेश्वर की संस्कृति, इतिहास और आस्था से परिचित कराया जा सके। मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एमकेआईटीएम) लखनऊ के सहयोग से एसडीआरएफ टीम द्वारा आयोजित तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 से 7 जनवरी तक नाविकों को आपदा प्रबंधन, आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार तथा ऑनलाइन पेमेंट जैसी आधुनिक सुविधाओं संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार बटेश्वर में ग्रामीण पर्यटन को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। नाविकों को स्टोरी टेलिंग, आपदा प्रबंधन और आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से जोड़कर हम उन्हें केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि बटेश्वर की संस्कृति, इतिहास और आस्था का संवाहक बना रहे हैं। इससे पर्यटकों का अनुभव और अधिक परिपक्व होगा, वहीं स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को हम केवल पर्यटन स्थलों तक सीमित न रखते हुए स्थानीय समुदायों को भी सहभागी बना रहे हैं। नाविकों के निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें कौशल, आत्मविश्वास और पहचान मिल रही है। हमारा लक्ष्य समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देते हुए जन सहभागिता और सामुदायिक भागीदारी को पर्यटन विकास की मजबूत आधारशिला बनाना है, ताकि पर्यटन का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

इसके अतिरिक्त कतर्नियाघाट एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मूलभूत ढांचा सुधारा गया है। बुंदेलखंड के रानीपुर टाइगर रिजर्व को नए ईको–टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

योगी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक नीतियां लागू की हैं। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसके कारण होटल, रिसॉर्ट एवं होमस्टे बनाने वाले निवेशकों को अनुदान, टैक्स में छूट और आसान ऋण की सुविधा प्राप्त हो रही है।

पर्यटकों की सुविधा के लिए वन–स्टॉप डिजिटल पोर्टल बनाए गए हैं, जहां बुकिंग, रूट एवं गाइड की जानकारी आसानी से प्राप्त होती है। यहां उन्हें यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है।

अयोध्या, वाराणसी एवं आगरा आदि शहरों में स्थानीय लोगों को अपने घरों को पर्यटकों के लिए होमस्टे

बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव प्राप्त होता है और स्थानीय रोजगार भी बढ़ता है।

पर्यटकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कनेक्टिविटी पर सराहनीय कार्य किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहरों को आपस में जोड़ दिया गया है। इससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिला है।

जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट विदेशी पर्यटकों के लिए सीधे रास्ते खोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुशीनगर एवं वाराणसी समेत कई घरेलू हवाई अड्डों का विस्तार किया गया है। प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे आगरा–मथुरा– काशी–अयोध्या के मध्य पर्यटकों के समय को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मत है कि पर्यटन से केवल एक स्थल विशेष का विकास नहीं होता, अपितु उस क्षेत्र के समग्र विकास एवं ईको–सिस्टम को गति मिलती है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, टैक्सी एवं रेस्टोरेंट आदि क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी एवं सुदृढ़ कानून– व्यवस्था भी आवश्यक है। सुरक्षित वातावरण एवं सुगम यात्रा के कारण ही प्रदेश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों का आगमन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है।

निःसंदेह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आज प्रदेश की आबादी से दोगुनी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। हम सभी को नया उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से हम केवल स्थल विशेष का विकास नहीं कर रहे, बल्कि इसके माध्यम से वहां के समग्र विकास, ईको सिस्टम और रोजगार को गति देने का भी काम कर रहे हैं। ◆

(लेखक लखनऊ वि.वि. में पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष हैं)

मो. : 8750820740

डबल इंजन सरकार में निरंतर विकसित होता यूपी

–सियाराम पांडेय 'शांत'

केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो क्या नहीं हो सकता? तेजी से विकसित होता उत्तर प्रदेश इसका प्रमाण है। कौन कितने दिन सत्ता में रहा, कितने दिन सत्ता में रहेगा, यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि उस दौरान उसने देश के लिए क्या किया और आगे क्या करने की उसकी योजना है। सरकार वैसे भी तुलना का विषय नहीं है, वह दूसरों की खींची विकास रेखा से अपनी रेखा को अपने काम से बड़ी करते रहने का नाम है। जनता के समग्र विकास और उनकी सुविधाओं के विस्तार में उसकी भूमिका क्या रही, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 148 करोड़ भारतीयों की सेवा करते हुए 12 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के मामले में उन्होंने पं. जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी के इस 12 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में तेज गति से प्रगति की है। सच्चाई तो यह है कि आज पूरा संसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की विकास यात्रा का कायल है। दुनिया भर के नेता उन्हें सबसे लंबे समय तक भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की बधाई दे रहे हैं। उनकी दृष्टि और नेतृत्व की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं।

जाति, पंथ, क्षेत्र या भाषा को दरकिनार कर उन्होंने जिस तरह भारत के विकास रथ को दिग्विजयी बनाने की दिशा में काम किया है, उससे सर्वाधिक लाभान्वित उत्तर प्रदेश हुआ है। कहना न होगा कि तीन माह पहले ही मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने भी नौ साल पूरे किए हैं और इस अवधि में डबल इंजन सरकार के काम उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से देखे–सुने और महसूस किए जा सकते हैं। गत 12 साल में अगर भारत बहुत तेजी के साथ विकसित हुआ है। उसने नवाचार के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है तो उत्तर प्रदेश ने देश के अन्य राज्यों को विकास के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश की योजना के तहत काम करता उत्तर प्रदेश आज हर आम और खास की जुबान पर है। तभी तो उसे विकसित भारत का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। भारत ने जहां विश्व स्तर पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है और अन्य देशों के लिए मॉडल बन रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश भी व्यापक पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के मामले में केंद्र सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को राज्य में शत–प्रतिशत लागू करने में योगी सरकार का कोई सानी नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 148 करोड़ भारतीयों की सेवा करते हुए 12 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के मामले में उन्होंने पं. जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी के इस 12 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में तेज गति से प्रगति की है। सच्चाई तो यह है कि आज पूरा संसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की विकास यात्रा का कायल है। दुनिया भर के नेता उन्हें सबसे लंबे समय तक भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की बधाई दे रहे हैं। उनकी दृष्टि और नेतृत्व की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं।

जब जाति और धर्म के नाम पर देश और प्रदेश को तोड़ने की साजिशें हो रही थीं, उस स्थिति में गरीब, महिला, युवा और किसान को ही जाति मानना नरेंद्र मोदी का बेहद साहसिक काम था। कहना न होगा कि उन्होंने विकसित भारत की अपनी अवधारणा को साकार करने के लिए जो योजनाएं बनाईं,उसमें इन्हीं चार वर्गों को वरीयता दी गई और इसका असर देश–प्रदेश में दिख भी रहा है। यही वजह है कि मोदी सरकार में 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। उनकी नजर में गरीब केवल गरीब है। वे उसे जाति और धर्म में बांटकर देखने के कभी भी हिमायती नहीं रहे। कमोवेश यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी लागू होती है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया।

मोदी सरकार में देश में जो भी योजनाएं बनी हैं, वे अटकी–लटकी और भटकी नहीं हैं बल्कि उनकी परिणिति उनके क्रियान्वयन की पूर्णता ही रही है। यूपी में तो केंद्रीय योजनाओं की पूर्णता की शत प्रतिशत गारंटी रही है। जनधन खातों के जरिए वित्तीय समावेशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, गरीबों के लिए घर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा और मुद्रा, स्टैंड–अप इंडिया, स्टार्ट–अप इंडिया, कौशल विकास योजना और डिजिटल इंडिया जैसी पहल कर एक तरह से उन्होंने देश को विकास के उच्च सोपान पर ले जाने का ही प्रयास किया है। इन कार्यक्रमों से देश लाभान्वित तो हुआ ही है लेकिन उत्तर प्रदेश भी कम फायदे में नहीं रहा है।

गरीबों को सशक्त बनाने, उन्हें सुस्थिर विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की दिशा में देश–प्रदेश में चौतरफा काम हुआ है। बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने जैसे कार्यक्रमों, मातृ कल्याण योजनाओं, महिला स्वयं–सहायता समूहों और महिला सशक्तीकरण की मुहिम से महिलाओं के लिए अवसरों के द्वार खुले हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने में नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी भूमिका रही है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सदियों पुराना सपना पीएम मोदी के सहयोग से ही संभव हो सका है। आस्था और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान यही सरकार कर सकती है, इस तरह का संदेश भारत ही नहीं, पूरे विश्व में गया है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, महाकाल लोक का विकास और केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण यह बताने और जताने के लिए काफी है कि भारत की सभ्यतागत विरासत को संरक्षित करने के प्रति केंद्र सरकार कितनी गंभीर है?

देश के 150 जिलों में फैले नक्सलवाद को समाप्त करने का श्रेय मोदी सरकार को ही जाता है। नक्सल प्रभावित जिन क्षेत्रों में कभी हिंसा का साम्राज्य था, आज वहां विकास, पर्यटन और निवेश हो रहा है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी शासन को तो देना ही पड़ेगा। कल्याण–केंद्रित शासन, आर्थिक बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास की बहाली ही नरेंद्र मोदी के जीवन का एक मात्र लक्ष्य रहा है। उन्हीं के नक्शेकदम पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं। उन्होंने यहां माफिया संस्कृति को कुचलने का जो साहसिक प्रयास किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है। तमाम राजनीतिक और विधिक अवरोधों के बावजूद

उनका बुलडोजर अपराध माफियाओं के हृदय में भय का संचार कर रहा है।

केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत जहां देश भर में 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं, 12 करोड़ से अधिक शौचालयों यानी इज्जतघर का निर्माण कर नारी गरिमा और सुविधा को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में काम किया है। मुद्रा योजना के लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग महिला उद्यमी हैं, इस सच को नकारा नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराकर 70 प्रतिशत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। लखपति दीदी, करोड़पति दीदी और स्वयं सहायता समूहों ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। वहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने राजनीति में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएम मोदी की सकारात्मक सोच का परिणाम यह है कि आज देश की आधी आबादी सेना, अंतरिक्ष, खेल, अनुसंधान और उद्योग सहित जीवन हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया, बल्कि तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया। कोरोना काल में समय से वैक्सीन बनवाकर उन्होंने कोरोना जैसी महाविनाशक बीमारी के क्रूर पंजों से न केवल भारतीयों का जीवन सुरक्षित किया बल्कि देश– दुनिया को भी कोरोना से निजात दिलाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विदेशों से विमान या सैन्य उपकरण खरीदने से पहले उसका एक्सेस भी मांगा, तकनीक भी मांगी जिससे कि वह उनका उपयोग देश के हिसाब से कर सकें। वैसे ही उत्पाद देश में तैयार कर सकें। और ऐसा वे कर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया फ्रांस यात्रा को कमोवेश इसी रूप में देखा जा रहा है। फ्रांस भारत को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में उभरकर सामने आया है। दोनों पक्ष भारत द्वारा अधिक पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की

खरीद जैसे महत्वपूर्ण रक्षा खरीद परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय ने लगभग दो वर्ष पहले ही करीब 36,000 करोड़ रुपये के इस समझौते को मंजूरी दे दी थी, लेकिन परियोजना के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पहलुओं को अंतिम रूप देने संबंधी बातचीत में देरी होती रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी देश को छेड़ेगा नहीं, लेकिन उस पर कोई आक्रामक होने की धृष्टता करेगा तो वह उसे छोड़ेगा भी नहीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन की नई परिभाषा गढ़ी है। पिछले 14 वर्षों में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार बढ़कर 1,000 किलो मीटर से अधिक हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इस अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में छह गुना वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की गई। भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है।

केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से यमुना की सफाई, बुनियादी ढांचे और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 12 वर्षों में समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से कमजोर तबकों के कल्याण के लिए काम किया है और उनका उत्थान सुनिश्चित किया है। ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते हुए क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी से पूरे देश में विकास का माहौल बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश की तस्वीर और तकदीर बदली है। एनडीए आज 22 राज्यों में सत्ता में है। इसे पीएम मोदी पर जनता का विश्वास नहीं तो और क्या कहा जाएगा? सरकार की प्राथमिकता गरीब, किसान, युवा एवं महिलाओं का कल्याण है। जनधन योजना के तहत देश में 58 करोड़ से अधिक बैंक

खाते खोले गए हैं, जबकि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 करोड़ से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना से 11 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों को नल से जल तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों को 4.3 लाख करोड़ रुपये सीधे खातों में हस्तांतरित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत ने विकास, अर्थव्यवस्था, तकनीक, आधारभूत संरचना, रक्षा, डिजिटल भुगतान, ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वहीं रक्षा निर्यात, मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और सौर ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। तीसरे कार्यकाल के दौरान बने ये रिकॉर्ड केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व क्षमता के भी परिचायक हैं। ये उपलब्धियां नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

14 मई, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी। लगभग 3,706 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना भारत की छठी स्वीकृत सेमीकंडक्टर यूनिट बनी। मोदी सरकार का यह निर्णय देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया। सेमीकंडक्टर आज मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण और रक्षा प्रणालियों सहित लगभग हर आधुनिक तकनीक की आधारभूत आवश्यकता है। यह सेमीकंडक्टर यूनिट विशेष रूप से डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का उत्पादन करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजित करेगी तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करेगी।

नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो गया। लगभग सम्पूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ भारत ने विश्व की सबसे बड़ी और सबसे तेज रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं में से एक को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

कहना न होगा कि उत्तर प्रदेश में रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वर्ष 2014 में जहां रेलवे के सीमित हिस्से का ही विद्युतीकरण हुआ था, वहीं एक दशक के भीतर यह कवरेज लगभग पूर्णता तक पहुंच गई। रेल विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ डीजल पर निर्भरता में कमी और परिचालन लागत में गिरावट के रूप में सामने आया है। इससे रेलवे की ऊर्जा दक्षता बढ़ी है और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है।

नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 898 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि वर्ष 2014 में यह केवल 3.68 मेगावाट थी। इस प्रकार लगभग 11 वर्षों में 240 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक नेट–जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में लगातार विस्तार किया जा रहा है। बढ़ती सौर ऊर्जा क्षमता से रेलवे की बिजली लागत में कमी आई है तथा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी घटी है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में यह प्रगति पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ परिचालन लागत कम करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

एक अप्रैल 2025 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का रक्षा

निर्यात बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह वित्त वर्ष 2023–24 के 21,083 करोड़ रुपये की तुलना में 12.04 प्रतिशत अधिक था। इसके साथ ही भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया और वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया। रक्षा मंत्रालय अब भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात लगभग 80 देशों में कर रहा है, जो भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2024–25 में निजी क्षेत्र ने 15,233 करोड़ रुपये तथा रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों ने 8,389 करोड़ रुपये के निर्यात में योगदान दिया।मिसाइल, रडार, गोला–बारुद, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, नौसैनिक प्रणालियां और एयरोस्पेस उपकरणों की बढ़ती मांग ने भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। विशेषज्ञों के अनुसार रक्षा निर्यात में यह निरंतर वृद्धि न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है, बल्कि भारत की सामरिक शक्ति, तकनीकी क्षमता और वैश्विक प्रभाव को भी मजबूत कर रही है।

अगर हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि की बात करें तो यहां की जीएसडीपी 2017 के बाद 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गई और प्रदेश की आर्थिक हिस्सेदारी 9.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मतलब 2017 के बाद मात्र आठ से साढ़े आठ वर्ष के बीच में डबल इंजन सरकार ने इसमें 23 लाख करोड़ अतिरिक्त जोड़े हैं। जब देश आजाद हुआ था, यूपी का शेयर 14 प्रतिशत था। घटते–घटते 2016–17 में यह आठ प्रतिशत रह गया था। यहां की प्रति व्यक्ति आय भी तीन गुना बढ़ी है।

पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना हुआ है। आज पिछले 11 वर्षों में किसानों के श्रम और कारीगरों की सृजनशीलता से यह देश खड़ा हुआ है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई स्पष्ट कृषि नीति नहीं थी। अन्नदाता केवल वोट बैंक बन गया था। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता को विकास में भागीदार बनाया। आज हालात यह है कि देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55 प्रतिशत उत्तर प्रदेश का किसान करता है। सन 2000 से 2017 के बीच 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ था, जबकि पिछले साढ़े आठ वर्षों में 3,06,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। यानी आधे समय में 90 हजार करोड़ अधिक भुगतान किया गया।

उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिलें संचालित हैं और गन्ने का मूल्य 400 प्रति कुंतल तक किया गया है. वहीं, एथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत शुगर–एथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बनाया गया है। प्रदेश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूती दी गई है। वर्तमान में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और कुछ स्थानों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए गए हैं। कृषि मंडी और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना आसान हुआ है। हर खेत को पानी देने के लिए नहरों, पाइपलाइन और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 31 बड़ी परियोजनाएं पूरी की गई हैं। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप और किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था की गई है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में डिजिटल इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री इकोसिस्टम को सशक्त किया गया है। एआई कृषि प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को उनकी भाषा में जानकारी देने की सरकार की योजना है। प्रदेश में एफपीओ गठित किए गए हैं जो खासतौर पर महिलाओं की सहभागिता के माध्यम से किसानों की आमदनी को बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार में यूपी द्रुत गति से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ♦

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

मो. : 7459998968

ऑपरेशन कायाकल्प और पारदर्शी भर्तियां

–देवराज सिंह

यूपी : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और नई पहचान देने का काम किया है। प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने से लेकर पारदर्शी शिक्षक भर्तियों, नकलविहीन परीक्षाओं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और मेधावी छात्रों को सम्मानित करने तक सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों पर दिखाई दे रहा है। सरकार का दावा है कि शिक्षा क्षेत्र में किए गए इन सुधारों का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है।

ऑपरेशन कायाकल्प ने बदली सरकारी स्कूलों की तस्वीर

योगी सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक ऑपरेशन कायाकल्प रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का व्यापक विकास किया गया है। पहले जिन विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर और साफ–सफाई जैसी सुविधाओं का अभाव था, वहां अब आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सरकार के अनुसार 96 प्रतिशत से अधिक परिषदीय विद्यालयों को इस अभियान के तहत संतृप्त किया जा चुका है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षण संसाधन और आकर्षक शिक्षण वातावरण विकसित किया गया है। इससे सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है और अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।

वर्षों से लंबित भर्तियों को मिली गति

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने शिक्षकों की नियुक्तियों पर भी विशेष ध्यान दिया है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से लंबित टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के कुल 33,401 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई गई है। इन नियुक्तियों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि योग्य शिक्षकों की उपलब्धता से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सकेगा। वर्षों से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को भी इससे राहत मिली है।

मिशन 'DEAR' से पढ़ने की आदत को बढ़ावा

डिजिटल युग में बच्चों के बीच मोबाइल और स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए सरकार ने "मिशन DEAR" (Drop Everything And Read) की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना और उनकी भाषा तथा समझने की क्षमता को मजबूत बनाना है। राज्य के करीब 1.5 लाख सरकारी विद्यालयों में छात्रों को नियमित रूप से अखबार पढ़ने, पुस्तकालयों का उपयोग करने और पुस्तकों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया

जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल बच्चों के बौद्धिक विकास और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मेधावी छात्रों को मिल रहा सम्मान

योगी सरकार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सम्मान योजनाएं शुरू की हैं। यूपी बोर्ड समेत अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मेधावी विद्यार्थियों को सार्वजनिक रूप से सम्मान देने से उनका मनोबल बढ़ता है और अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलती है। इससे शिक्षा के प्रति सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार हो रहा है।

कन्या शिक्षा को मिला विशेष प्रोत्साहन

बालिका शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार किया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और दूरदराज क्षेत्रों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में नए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है जहां छात्राओं के लिए शिक्षा तक पहुंच पहले सीमित थी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बेटी की शिक्षा केवल भौगोलिक या आर्थिक कारणों से प्रभावित न हो।

शिक्षकों और कर्मचारियों को मिला संबल

शिक्षा व्यवस्था की सफलता में शिक्षकों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ने उनके हितों पर भी ध्यान दिया है। अनुदेशकों, शिक्षामित्रों तथा बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि उन्हें अधिक सुरक्षा और सम्मान का भी अनुभव हुआ है। सरकार का मानना है कि संतुष्ट और प्रेरित शिक्षक ही विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

नकलविहीन परीक्षाओं से बढ़ी विश्वसनीयता

योगी सरकार के कार्यकाल में बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की निगरानी, सीसीटीवी कैमरों का उपयोग और तकनीकी संसाधनों के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाया गया है। इन प्रयासों का परिणाम यह रहा है कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और योग्य विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप अवसर मिलने लगे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत

शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास, पारदर्शी भर्तियों, बालिका शिक्षा, डिजिटल शिक्षण और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित योजनाओं के माध्यम से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। इन पहलों ने प्रदेश को शिक्षा सुधार के क्षेत्र में एक नए मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का प्रभाव प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ◆

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
मो. : 9415000913

विकास की ओर बढ़ता दंगामुक्त उत्तर प्रदेश

–प्रमिला

उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी ने सन् 2017 में सत्ता संभाली। तब से अब तक अपने संकल्प पत्र (लोक कल्याण पत्र) में कानूनी व्यवस्था में सुधार कर अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की स्थापना का वादा किया, जिस पर योगी सरकार सौ फीसदी खरी उतरी।

उत्तर प्रदेश का शासन मुख्यमंत्री योगी को मलवे के रूप में मिला है, मलवे को हटाने और किसी नये निर्माण के लिए नींव रखने में कुछ समय लगता है। योगी जी को विरासत में मिली है अराजकता, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिक उन्माद, साम्प्रदायिक दंगों की श्रृंखला, राजनीति का अपराधीकरण, घनघोर आर्थिक संकट, इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद योगी सरकार की पहली प्राथमिकताएं, इसमें सबसे ऊपर रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम, प्रत्येक नागरिक की जान–माल और उसकी सुरक्षा की गारन्टी। अगर देखा जाये तो इतने बिगड़े हुए माहौल के बावजूद कानून और व्यवस्था की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधों को पांच श्रेणियों में बांटा है और प्रत्येक श्रेणी के अपराधों से अलग से निबटने का प्रयत्न हो रहा है, ये श्रेणियों हैं–(1) साम्प्रदायिक दंगे (2) आतंकवाद (3) माफिया सरगनाओं की काली छाया (4) अपहरण और (5) अन्य छोटे–मोटे अपराध।

सन् 2017 से पहले स.पा. एवं ब.स.पा. सरकार में उ.प्र. में अपराधियों का बोलबाला था, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक फैल चुका था। इससे न तो उद्यमी राज्य की ओर रुख

कर रहे थे और न ही निवेश हो रहा था। सूबे का खजाना खाली था। योगी सरकार ने समझ लिया था कि स्थिति विकट है इस स्थिति से उबरने के लिए पुलिस अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। जिससे उत्तर प्रदेश अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं दंगामुक्त हुआ। प्रदेश में सुशासन की स्थापना हुई, अपराधियों के अन्दर यूपी पुलिस का खौफ अभी भी बरकरार है। प्रदेश में पुलिस के डर से बड़े–बड़े अपराधी और माफिया प्रदेश को छोड़कर या तो भाग गये या आत्मसर्पण कर दिये हैं। पहले उत्तर प्रदेश को दंगों और गुण्डागर्दी का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन योगी सरकार में अभी तक एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ है। अपराधियों के प्रति जीरो टालरेन्स नीति और भ्रष्टाचार पर प्रहार दंगा की नीति का यह असर है। सरकार ने जीरो टालरेन्स नीति के कामकाज की एक शैली के रूप में स्थापित कर दिया। पूरे प्रदेश में कानून का राज है. भाजपा के लोक कल्याण पत्र में गुण्डाराज को जड़ से खत्म करने का वादा किया था। सी. एम. योगी ने न सिर्फ भा.ज.पा. के संकल्प पत्र के वादे को पूरा किया, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर भविष्य में माफियाओं और गुण्डों के लिए यू.पी. की राह बन्द कर दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था अपराधी या जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर। कभी पुलिस प्रशासन को आँख दिखाने वाले माफियाओं, अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूटी है। अपराधियों पर कार्यवाही हो या फिर लवजिहाद का मुद्दा, बूचड़खानों से पुलिस ने सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही नहीं, बल्कि प्रदेश के दो दर्जन से अधिक बड़े माफियाओं के जेल में धकेल कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शत्रु सम्पत्ति पर कब्जे की शिकायतों को भी बहुत गम्भीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि विभिन्न जनपदों में स्थित शत्रु सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी ने शत्रु सम्पत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए गृह विभाग की निगरानी में प्रदेश व्यापारी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह दावा लगातार करते रहे हैं कि यू.पी. में संगठित अपराध खत्म हो गया है। ऐसे अपराधी या जेल में बन्द हैं या फिर मारे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी इसका श्रेय अपनी सरकार की जीरो टॉलरेन्स की नीति और पुलिस की सक्रियता को देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे की पुष्टि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी किए गए वर्ष 2021 के आंकड़ों ने भी की है। इन आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2021 में साम्प्रदायिक हिंसा का सिर्फ एक मामला आया, जबकि झारखण्ड में 100 मामले, महाराष्ट्र में 77 और राजस्थान में 22 मामले सामने आए।

एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में गिरावट आयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश 28 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में 2845 मामलों के साथ बलात्कार के मामले में 23वें और हत्या में 24 वें स्थान पर है। इसके अलावा, देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद 16,838 मामलों के साथ बच्चों के खिलाफ अपराध में 28वें और फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 36 वें स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शत्रु सम्पत्ति पर कब्जे की शिकायतों को भी बहुत गम्भीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि विभिन्न जनपदों में स्थित शत्रु सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी जी ने शत्रु सम्पत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए गृह विभाग की निगरानी में प्रदेश व्यापारी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक प्रतिज्ञा भी है और कहा है कि मैंने कसम खाई है कि अपराध को समाप्त करूंगा। रामपुर के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के खिलाफ कठोर कारवाई को मुख्यमंत्री की उसी प्रतिज्ञा का परिणाम माना जा रहा है। अपराधियों के साथ ही साथ उनके सहयोगी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ

कार्यवाही भी मुख्यमंत्री योगी द्वारा की जा रही है।

कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ 1.38 लाख पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के साथ ही सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क और 213 नये थानों का निर्माण हुआ है। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी व कानपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया। एन्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन कर आरोपियों पर कार्यवाही की। साथ ही प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही योगी सरकार ने महिलाओं से जुड़े अपराधों पर तुरन्त कारवाई का एक रिकार्ड बनाया है।

जहां पिछली सरकारों में भू–माफिया और अपराधी

सत्ता का संरक्षण पाते थे, वहीं योगी सरकार ने माफियाओं की काली कमाई से अर्जित की गई 1800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्तियों को जब्त अथवा ध्वस्त किया है। 2017 के पहले तक अराजकता और दंगों के लिए जाने जाने वाला प्रदेश में आज पूरी तरह से शान्ति कायम है। सभी पर्व और त्यौहार शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो रहे हैं। राज्य में दहशत का पर्याय बना रहे। करीब 150 से अधिक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और लगभग 2800 से अधिक अपराधी घायल हुए हैं। यू.पी. में गैंगस्टर एक्ट में अब तक 3700 से अधिक अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत् कार्यवाही हुई है। यू.पी. सरकार और पुलिस ने जिस तरीके से राज्य में संगठित अपराध और माफियाओं पर अंकुश लगाया है, वह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी जी साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर जिले में साइबर क्राइम थाना बनाए जाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये थाने स्थानीय सुविधानुसार जिलों की रिजर्व पुलिस लाइन में स्थापित किये जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राज्य स्तर पर संयुक्त साइबर को ऑर्डिनेशन टीम गठित की जाए। मुख्यमंत्री योगी जी ने आदेश दिया है कि पुलिस विभाग के अलावा साइबर विभाग के अधिकारियों को भी इस टीम में शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों से कहा है कि अन्तर्राज्यीय और यू.पी. से जुड़े दूसरे राज्यों की सीमा से जुड़े जिलों को वाइब्रेंट बनाने के लिए नियोजित तरीके से प्रयास किया जाए। उन्होंने सीमावर्ती गांवों और जिलों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि स्कूली बच्चों, एन.सी.सी. कैडेट्स और एन.एस.एस. कैडेट्स के जवानों को इन क्षेत्रों में घुमाया जाए। इसके अलावा इन क्षेत्रों के रिटायर्ड सैन्य कर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवानों को सरहद के सिपाही के तौर पर पहचान दी जाए ताकि व्यवस्था सुधारने के क्रम में आवश्यकता पड़ने पर इनका भी सहयोग लिया जा सके। ♦

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

मो. : 9453059581

विदेश की राह छोड़ी, लौटे अपने गांव

–वीरेन्द्र पाठक

प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के हरवारी लखनपुर गाँव के रहने वाले जिज्ञासु मिश्रा आज आधुनिक खेती के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले युवाओं में शामिल हो चुके हैं। एमकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कतर, सिंगापुर सहित कई देशों की नामी इंटरनेशनल कंपनियों में काम किया। विदेशों में बेहतर वेतन और सुविधाओं के बावजूद उनके मन में हमेशा अपने देश लौटकर कुछ बड़ा और अलग करने की इच्छा बनी रही।

विदेश में काम करते हुए उन्होंने करीब से देखा कि कैसे तकनीक और प्रबंधन के जरिए खेती को एक लाभकारी उद्योग बनाया जा सकता है। इसी सोच ने उन्हें प्रेरित किया और पुणे के अपने परिचितों से उन्हें नियंत्रित तापमान (पॉलीहाउस) में खेती का विचार मिला। यही विचार उनकी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ।

शुरुआत : 25 लाख का निवेश और संघर्ष भरी नींव

गाँव लौटने के बाद जिज्ञासु मिश्रा ने मेजा में जमीन खरीदी और पॉलीहाउस के लिए आवेदन किया। पहले ही वर्ष उन्होंने करीब 25 लाख रुपये का निवेश कर अपना पहला पॉलीहाउस तैयार कराया। यह सफर आसान नहीं था। जमीन पथरीली थी और बोरिंग कराने में कई बार पानी नहीं मिला। कई प्रयास असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः पानी मिलने के बाद ही आगे बढ़े।

उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यान विभाग से उन्हें अनुदान और तकनीकी सहायता मिली, जिससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। मात्र तीन महीने में करीब 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में उनका पहला पॉलीहाउस तैयार हो गया। यहाँ उन्होंने लाल और पीली शिमला मिर्च की खेती शुरू की।

कोविड का झटका, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी

जब उनकी मेहनत रंग लाने ही वाली थी, तभी कोविड–19 महामारी ने सब कुछ बदल दिया। बाजार बंद हो गए और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। हालात ऐसे

उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यान विभाग से उन्हें अनुदान और तकनीकी सहायता मिली, जिससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। मात्र तीन महीने में करीब 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में उनका पहला पॉलीहाउस तैयार हो गया। यहाँ उन्होंने लाल और पीली शिमला मिर्च की खेती शुरू की।

बने कि उन्हें अपनी उपज गायों को खिलानी पड़ी और कुछ लोगों में मुफ्त बांटनी पड़ी।

यह किसी भी किसान के लिए टूट जाने जैसा समय था, लेकिन जिज्ञासु मिश्रा ने इसे अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत माना।

रणनीति में बदलाव और नई सफलता की शुरुआत

उन्होंने अपनी रणनीति बदली और फूलों की खेती की ओर कदम बढ़ाया। पुणे के परिचितों से तकनीक सीखकर उन्होंने गुलाब की खेती शुरू की। शुरुआत में पौधे पुणे से मंगवाए, लेकिन धीरे–धीरे उन्होंने खुद की नर्सरी विकसित कर ली। अब वे अपने पौधे खुद तैयार करते हैं, जिससे लागत कम हुई और गुणवत्ता पर नियंत्रण बढ़ा।

लगातार विस्तार : अब चार पॉलीहाउस

पहले पॉलीहाउस पर मिले अनुदान और अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने दूसरे पॉलीहाउस के लिए प्रस्ताव भेजा और धीरे–धीरे अपने प्रोजेक्ट का विस्तार किया।

आज उनके पास कुल मिलाकर :

1000 वर्ग मीटर का एक पॉलीहाउस

3000 वर्ग मीटर का एक पॉलीहाउस

4000–4000 वर्ग मीटर के दो बड़े पॉलीहाउस

इस तरह वे अब बड़े स्तर पर नियंत्रित तापमान में खेती कर रहे हैं और लगातार अपने काम को बढ़ा रहे हैं।

आमदनी का मजबूत जरिया और रोजगार सृजन

आज जिज्ञासु मिश्रा करीब दो बीघे से अधिक क्षेत्र में पॉलीहाउस खेती कर हर साल लगभग 25 लाख रुपये तक की आमदनी कर रहे हैं। इसमें लगभग 25 प्रतिशत लागत निकल जाती है, जबकि बाकी शुद्ध मुनाफा होता है।

उनकी इस पहल का सबसे बड़ा प्रभाव रोजगार के रूप में सामने आया है–

8 मजदूर स्थायी रूप से कार्यरत हैं, जिन्हें सालभर नियमित काम मिलता है इसके अलावा स्थानीय स्तर पर कई लोगों को समय–समय पर रोजगार मिलता है अब उनका पूरा परिवार भी इस काम में सक्रिय रूप से जुड़ चुका है, जो

नर्सरी, कटिंग, पैकिंग और देखभाल जैसे कार्यों में उनका सहयोग करता है इस तरह उनका यह काम एक सफल पारिवारिक और सामुदायिक उद्यम बन चुका है।

पॉलीहाउस में खेती कैसे होती है?

जिज्ञासु मिश्रा बताते हैं कि पॉलीहाउस खेती पूरी तरह वैज्ञानिक और नियंत्रित प्रक्रिया है। इसमें : तापमान और नमी को नियंत्रित किया जाता है, जिससे हर मौसम में खेती संभव होती है प्लास्टिक शीट से ढके ढांचे में पौधों को तेज गर्मी, ठंड और बारिश से बचाया जाता है ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम के जरिए पानी और पोषक तत्व सीधे जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं। पौधों की कटिंग (प्रूनिंग), ग्रोथ कंट्रोल और नियमित देखभाल की जाती है। कीट और बीमारियों पर भी वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रण रखा जाता है। वे बताते हैं कि गर्म क्षेत्रों जैसे प्रयागराज में भी पॉलीहाउस के जरिए सालभर उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उगाई जा सकती हैं, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है।

बाजार में मजबूत पकड़

उनके गुलाब और विदेशी सब्जियों की मांग सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि बड़े बाजारों तक है। उनके ग्राहक : दिल्ली की आजाद मंडी फाइव स्टार होटल्स अन्य बड़े व्यापारी हैं। वे बताते हैं कि दिसंबर से फरवरी तक गुलाब के फूलों के सबसे अच्छे दाम मिलते हैं, जबकि बाकी समय मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमत तय होती है।

नई शुरुआत करने वालों के लिए संदेश

जिज्ञासु मिश्रा का मानना है कि पॉलीहाउस खेती में सफलता के लिए : पहले इसकी बारीकियां सीखना जरूरी है। पौधों की कटिंग और देखभाल की तकनीक समझनी चाहिए। शुरुआत छोटे स्तर से करनी चाहिए और सब्जियों से शुरुआत करना अधिक सुरक्षित रहता है। कई देशों में नौकरी करने के बाद जिज्ञासु मिश्रा ने देश प्रेम और आत्मनिर्भर बनने की सोच के साथ अपने गाँव लौटने का निर्णय लिया। आज वे न केवल खुद सफल उद्यमी बन चुके हैं, बल्कि अपने गाँव के कई लोगों को रोजगार देकर उनकी जिंदगी भी बदल रहे हैं।

उनकी यह प्रेरक कहानी बताती है कि अगर सोच बड़ी हो, तकनीक का सही उपयोग हो और मेहनत में निरंतरता हो, तो गाँव की जमीन भी सोना उगल सकती है। •

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
मो. : 9005902020

विकसित भारत की यात्रा

–पूजा गुप्ता

(लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 2014 से 2026 एक ऐसे युग का पर्याय बन गया है जिसने संकल्पों की सिद्धि का नया अध्याय लिखा है। यह साक्षी बन गया है क्रांतिकारी परिवर्तनों का और आज देश का जन–जन इन परिवर्तनों में खुद को सहभागी महसूस कर पा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष की उपलब्धियां, तप–तपस्या से निकला वह अमृत है, जो अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कटिबद्ध होकर कर चुका है नवनिर्माण की ओर प्रस्थान...)

राष्ट्र की विकास यात्रा में एक समय ऐसा जरूर आता है जब देश स्वयं को नए सिरे से परिभाषित करता है। नए संकल्प लेता है, प्रसिद्धि का मार्ग ढूंढता है। दृढ़ इच्छाशक्ति से उसे साकार करने में जुट जाता है। यहीं से कुछ ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं, जो युगों–युगों तक जन–जन की स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। वर्ष 2014 में देश की राजनीति ने करवट ली। देश ने एक ऐसी भोर देखी जहां से शुरू हुई विकास यात्रा आज भी अनवरत जारी है। विकसित भारत के एक विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे राष्ट्र के नवनिर्माण की इस यात्रा के 9 जून को 12 वर्ष पूर्ण हो गए। भारत की संस्कृति और अलग–अलग धर्म के शास्त्रों में 12 के अंक का एक विशेष महत्व भी है। शास्त्रों में 12 वर्ष की तपस्या का उद्देश्य साधक को आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म–साक्षात्कार में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 12 वर्ष की तपस्या एक कठोर और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है और हर कोई इसे करने में सक्षम नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष की विकास यात्रा केवल तात्कालिक समय की जरूरत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुविचारित दृष्टिकोण पर आधारित रही है।

दरअसल, बीते 12 वर्षों में सेवा ही संकल्प और कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की सोच ने ही पुरानी धारणाओं को तोड़ विकास के नए पथ का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीते 12 वर्षों में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने और सही अर्थों में आजादी का अहसास कराने की पहल हुई है, उसने पत्थर पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जो आजादी के अमृत काल से शुरू होकर स्वर्णिम वर्ष तक की यात्रा में नए भारत की नई तकदीर लिखने वाली है। एक ऐसा नया भारत जो युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान दे रहा है, नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, गरीबों के लिए आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई

मिल रही है। अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। बीते 12 वर्ष में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों के घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत तक की ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है, वह निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। पहले की तुलना में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह सफर यहीं पूरा नहीं होता है। देश को पूर्णता तक जाना है। इसी संकल्प के साथ भारत ने अमृत काल की यात्रा प्रारंभ की है जहां शत–प्रतिशत गांवों में सड़कें हों, शत–प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत–प्रतिशत पात्र जरूरतमंद के पास आयुष्मान भारत कार्ड हो, शत–प्रतिशत पात्र व्यक्तियों के पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो या आवास योजना हर उस व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ना है जो इसके हकदार हैं। पटरी और फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने वालों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। देश आज हर घर नल से जल मिशन को लेकर तेजी से काम कर रहा है। सर्वांगीण–सर्वसमावेशी– सर्वस्पर्शी विकास की सोच से केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति, वर्ग न छूटे, कोई भू–भाग, देश का कोई कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। चाहे नारी शक्ति हो या युवा शक्ति, किसान हो या गरीब–वंचित, सोच केवल एक ही है– विकास सर्वांगीण होना चाहिए। देश के ऐसे क्षेत्रों को भी आगे लाने के लिए पिछले 12 वर्षों में प्रयास किए गए हैं। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र, आदिवासी अंचल, भविष्य में भारत की विकास यात्रा के बहुत बड़े आधार बन रहे हैं। इन सभी के लिए सुशासन का ऐसा मंत्र हो जो बहुमत की बजाए सर्वसम्मति की सोच को बढ़ावा देता है और "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" जिसका ध्येय वाक्य बन चुका है। एक ऐसे भारत के निर्माण की ओर राष्ट्र बढ़ रहा है जहां गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्ति मिले।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर कई मंचों पर ऐसे कामों की सूची गिना चुके हैं जो आजादी के शुरुआती वर्षों में ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन उनके बारे में स्थायी समाधान की दीर्घकालिक सोच तब नहीं अपनाई गई। ऐसे में जो काम सात दशकों से लंबित या कहें कि अटके–लटके पड़े थे, उसे मौजूदा नेतृत्व में देश आज साकार होते हुए देख रहा है। अब देश को नियति के भरोसे नहीं बल्कि एक स्पष्ट सोच, दीर्घकालिक नीति और स्थायी समाधान के दृष्टिकोण से विकास की नई परंपराएं स्थापित हो रही हैं।

विकसित भारत का मजबूत होता मार्ग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर कई मंचों पर ऐसे कामों की सूची गिना चुके हैं जो आजादी के शुरुआती वर्षों में ही हो जाने चाहिए थे। लेकिन उनके बारे में स्थायी समाधान की दीर्घकालिक सोच तब नहीं अपनाई गई। ऐसे में जो काम सात दशकों से लंबित या कहें कि अटके–लटके

राष्ट्र की विकास यात्रा में एक समय ऐसा जरूर आता है जब देश स्वयं को नए सिरे से परिभाषित करता है। नए संकल्प लेता है, प्रसिद्धि का मार्ग ढूंढता है। दृढ़ इच्छाशक्ति से उसे साकार करने में जुट जाता है। यहीं से कुछ ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं, जो युगों-युगों तक जन-जन की स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। वर्ष 2014 में देश की राजनीति ने करवट ली। देश ने एक ऐसी भोर देखी जहां से शुरू हुई विकास यात्रा आज भी अनवरत जारी है। विकसित भारत के एक विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे राष्ट्र के नवनिर्माण की इस यात्रा के 9 जून को 12 वर्ष पूर्ण हो गए।

पड़े थे, उसे मौजूदा नेतृत्व में देश आज साकार होते हुए देख रहा है। अब देश को नियति के भरोसे नहीं बल्कि एक स्पष्ट सोच, दीर्घकालिक नीति और स्थायी समाधान के दृष्टिकोण से विकास की नई परंपराएं स्थापित हो रही हैं। इससे उदीयमान नए भारत का निर्माण हो रहा है। बीते 12 वर्षों में भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना किया है, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण तेज गति से विकास भी किया है। बीते 12 साल में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया गया है। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। उत्तर में देखें तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक, चिनाब ब्रिज बना है। पश्चिम में देखें तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी-ब्रिज, अटल सेतु बना है। पूर्व में देखें तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे। दक्षिण में देखें तो दुनिया के गिने-चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक, पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। इसी तरह, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही हैं। इस विकास के पीछे एक सोच है- जब भारत का प्रत्येक क्षेत्र आपस में जुड़ता है तो विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग मजबूत होता है। नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण बना है। इस नए भवन में पहला बिल महिलाओं को संसद-विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय के साथ पारित हुआ। इसी तरह 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की ओर बढ़ते भारत के कदम का परिचायक है। तीन तलाक, राम मंदिर, बोडो समझौता, अनुच्छेद 370 जैसे कई फैसलों से अमन-शांति स्थापित हुई। ऐसे फैसले जो दशकों से लंबित थे, जिन्हें स्थायी समस्या मान लिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समाधान निकला और नए भारत का अभ्युदय हो रहा है।

तकनीक से परिवर्तन का नया युग

भारत उन चंद देशों में शुमार है, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी नीतियों को बनाने में सबसे आगे है। कई क्षेत्र जिनमें टेक्नोलॉजी का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तकनीक से पारदर्शिता के नए

अध्याय की शुरुआत हुई है। आज भारत के ग्रामीण इलाकों में शहरों से अधिक इंटरनेट डेटा की खपत हो रही है। कोविड काल में यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को नई गति मिलने से डिजिटल लेन–देन को लोगों ने संस्कृति बना लिया। ई–कॉमर्स के माध्यम से व्यापक बाजार की उपलब्धता बढ़ी है। तकनीक की वजह से ही आज शत–प्रतिशत लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि पहले कहा जाता था कि एक रुपये में गांव तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। योजनाओं का क्रियान्वयन हो या निगरानी, तकनीक गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति की शक्ति प्रदान कर रही है। आईटी–फेसलेस असेसमेंट जैसी सुविधाओं ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं तो ई–ऑफिस जैसी पहल ने प्रशासन की गति को तेज किया है। गांवों में पोस्टल बैंक, स्कूलों में अटल इनोवेशन मिशन से नई संस्कृति की शुरुआत हुई। एक समय भारत में नौकरी मांगने वाली सोच थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे बदलकर नौकरी देने वाला बनाया। स्टार्टअप और मुद्रा की सहूलियत से आज युवा नई उड़ान भर रहे हैं। भारत में पहले स्टार्टअप शब्द गिने–चुने लोग ही समझते थे, लेकिन आज गांव तक युवा इसे समझ रहा है और अब यूनीकॉर्न बनने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईको–सिस्टम बन गया है।

वैश्विक नेतृत्व का अनुकूल अवसर

बीते 12 वर्षों में भारत का मान देश और दुनिया में बढ़ा है और भारत एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर उभरा है। रूस–यूक्रेन युद्ध के संकट काल में ऑपरेशन गंगा, ग्लासगो में कॉप–26 और शर्म–अल–शेख में कॉप 27 की बैठक में विकासशील देशों की मुखर आवाज बनकर उभरा भारत, संयुक्त राष्ट्र, बिम्सटेक, जी–20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की तरफ दुनिया की निगाह, इसकी मिसाल है। जी–20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने दुनिया को नई राह दिखाई है और विश्व को भारत की संस्कृति के साथ–साथ सामर्थ्य की भी अनुभूति कराई है। पर्यावरण के क्षेत्र में मिशन लाइफ और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल ने दुनिया को प्रकृति व वन्यजीवन के साथ समन्वय का मार्ग दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ संकट की घड़ी में पड़ोसी और दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत पहला मददगार राष्ट्र बना है तो कोविड काल में दुनिया के लिए औषधि का केंद्र बना था। बीते 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वहीं देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर ऐसा माहौल बना है कि आम

नागरिक केंद्र सरकार की योजनाओं में सहभागी बनकर विकास का भागीदार बन गया है।

निश्चित रूप से युगदृष्टा और साहसिक सुधारवाद के प्रणेता के तौर पर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'नए विश्वास के साथ नई शुरुआत' के प्रतीक बन चुके हैं। एक सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील भारत के निर्माण की पहल 'नया भारत, विकसित भारत' का विजन है। बीते 12 वर्ष में केंद्र सरकार के संकल्पों को आज प्रत्येक भारतवासी साकार होते देख रहा है। ◆

(लेखिका साहित्यकार एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं)
मो. : 7007224126

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना : संरक्षण से सशक्तीकरण तक

–डॉ. शिवानी कटारा

कभी–कभी एक योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं होती, बल्कि टूटते हुए सपनों को संभालने और बिखरते हुए जीवन को नई दिशा देने का संकल्प बन जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों के लिए आशा का उज्ज्वल दीप है, जिनकी दुनिया माता–पिता के बिछड़ जाने से अंधकारमय हो गई थी। जिन बच्चों के सपने अभावों की धूल में दबने लगे थे, जिनकी शिक्षा और सुरक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, उनके लिए यह योजना स्नेहिल अभिभावक बनकर सामने आई।

शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का समग्र मॉडल

30 मई 2021 को, जब कोविड–19 महामारी ने असंख्य परिवारों को गहरे शोक और अनिश्चितता के सागर में धकेल दिया था, तब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) अनाथ और असहाय बच्चों के जीवन में विश्वास और सहारे का नया अध्याय लेकर आई। अधिकांश योजनाएँ केवल आर्थिक सहायता तक सीमित रहती हैं, जबकि यह योजना बच्चों के जीवन के विभिन्न पहलुओं–भरण–पोषण, शिक्षा, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा–को एक साथ संबोधित करती है। बाद में योजना का विस्तार करते हुए इसके दायरे में उन निराश्रित और संकटग्रस्त बच्चों को भी स्थान दिया गया, जिनके जीवन से किसी अन्य कारणवश माता–पिता अथवा अभिभावकों का संरक्षण उठ गया था। इस पहल ने अनेक अनाथ बच्चों को यह भरोसा दिलाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी समाज और सरकार उनके साथ खड़ी है। आज यह योजना उत्तर प्रदेश में बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और संवेदनशील शासन का एक सशक्त मॉडल बन चुकी है।

वर्ष 2025–26 के बजट में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए ₹252 करोड़ की व्यवस्था की गई। यह केवल एक वित्तीय प्रावधान नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों के प्रति राज्य की संवेदनशील प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिनके जीवन में परिस्थितियों ने समय से पहले संघर्ष और जिम्मेदारियाँ ला दीं।

आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत लगभग डेढ़ लाख बच्चों तक सहायता पहुँच चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत लगभग 90,000 बच्चों को प्रतिमाह ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि कोविड–19 के कारण माता–पिता अथवा अभिभावकों को खो चुके बच्चों को ₹4000 प्रतिमाह की सहायता मिल रही है। योजना की विशेषता केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है। बच्चों की शिक्षा निरंतर बनी रहे, इसके लिए 1 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इन संस्थानों में शिक्षा के साथ–साथ आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे बच्चों को सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और परिवार जैसे वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।

आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत लगभग डेढ़ लाख बच्चों तक सहायता पहुँच चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत लगभग 90,000 बच्चों को प्रतिमाह ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि कोविड–19 के कारण माता–पिता अथवा अभिभावकों को खो चुके बच्चों को ₹4000 प्रतिमाह की सहायता मिल रही है। योजना की विशेषता केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है। बच्चों की शिक्षा निरंतर बनी रहे, इसके लिए 1 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

बालिकाओं के सशक्त भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके विवाह हेतु ₹1. 01 लाख की सहायता राशि का भी प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आर्थिक कठिनाइयाँ उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों में बाधा न बनें। बेटियों के प्रति सरकार की यह पहल केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि आत्मीय संरक्षण का भाव भी समेटे हुए है। एक अभिभावक की तरह राज्य उनके जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर साथ खड़ा होकर उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की ओर बढ़ने का विश्वास देता है। कोविड–19 महामारी में अनाथ हुई एक बालिका की संरक्षिका की यह बात योजना के प्रभाव को सहज ही व्यक्त करती है, 'जब हमें लगा कि बेटी के भविष्य की चिंता अकेले नहीं संभाल पाएंगे, तब इस योजना ने हमें सहारा दिया। आज उसकी पढ़ाई भी जारी है और उसके आने वाले कल को लेकर मन में भरोसा भी है।'

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की एक विशेषता इसकी मजबूत निगरानी व्यवस्था है। लाभार्थी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल की हर छह माह में समीक्षा की जाती है, जिससे सहायता उनके समग्र विकास तक प्रभावी रूप से पहुँच सके। योजना की आवेदन प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया गया है। योजना को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से अब पात्र लाभार्थी अथवा उनके संरक्षक आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है।

डिजिटल सपनों को पंख

योजना की सबसे प्रेरक उपलब्धियों में से एक बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है। कक्षा 9 अथवा उससे ऊपर अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने "बाल सेवा योजना" के लाभार्थी बच्चों को लैपटॉप वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया, वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी बड़ी संख्या में बच्चों को लैपटॉप उपलब्ध कराए गए हैं।

यह पहल केवल एक उपकरण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को डिजिटल युग की मुख्यधारा

से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रही है। इसके माध्यम से वे ऑनलाइन अध्ययन, ई–लर्निंग संसाधनों और आधुनिक शिक्षा के विविध अवसरों से जुड़ पा रहे हैं। लैपटॉप ने उनके लिए स्मार्ट अध्ययन, समृद्ध शैक्षिक सामग्री, नवीनतम जानकारियों और व्यापक ज्ञान–संसार के द्वार खोल दिए हैं। इससे वे न केवल अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी बना रहे हैं, बल्कि बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने का आत्मविश्वास भी प्राप्त कर रहे हैं। रामपुर के सुभाष गेट क्षेत्र की कक्षा 11 की छात्रा तनिषा सक्सेना इसकी एक प्रेरक मिसाल हैं। जिला प्रशासन द्वारा लैपटॉप प्राप्त करने के बाद उनके लिए पढ़ाई के नए रास्ते खुल गए। तनिषा कहती हैं, 'पहले पढ़ाई के लिए मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं खुद ऑनलाइन पढ़ाई कर पाती हूं। लैपटॉप मिलने से पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। इस सहयोग ने मेरे भीतर आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने का नया हौसला जगाया है।'

तनिषा की कहानी केवल एक छात्रा की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों की कहानी है जिनके लिए डिजिटल उपकरण अवसरों की नई दुनिया लेकर आए हैं।

जनपदों में बदलती जिंदगियां

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का प्रभाव प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रयागराज जनपद में 1468 से अधिक बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें 406 बच्चे कोविड महामारी में अपने माता–पिता को खो चुके हैं। प्रयागराज की एक लाभार्थी छात्रा बताती है, 'एक समय लगा था कि मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे, लेकिन अब मुझे अपने भविष्य पर भरोसा है। मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूं।'

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का प्रभाव प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जालौन जनपद में योजना के अंतर्गत प्रभावित बच्चों को ₹1.62 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वितरित की गई। वहीं कौशाम्बी के 668 बच्चे, जिनमें 64 कोविड से अनाथ हुए बच्चे शामिल हैं, इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। फतेहपुर के 645 बच्चों, जिनमें 78 कोविड अनाथ बच्चे हैं, तथा प्रतापगढ़ के 917 बच्चों, जिनमें 168 कोविड अनाथ बच्चे शामिल हैं, तक भी इस योजना का संरक्षण पहुंच रहा है। इसी प्रकार वाराणसी जनपद में 2,616 लाभार्थियों को ₹215.38 लाख से अधिक की सहायता प्रदान की गई। साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के पात्र 160 बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए।

योजना का दायरा केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है, जिन्होंने माता–पिता अथवा अभिभावकों को खो दिया है और जो स्नातक, डिप्लोमा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। NEET, JEE और CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले युवाओं को भी योजना के अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है, ताकि आर्थिक अभाव उनकी प्रतिभा और आकांक्षाओं के मार्ग में बाधा न बन सके। वाराणसी की लाभार्थी बालिका की माता शिप्रा सिन्हा बताती हैं, 'कोविड काल में पति के निधन के बाद बेटी की पढ़ाई को लेकर काफी चिंता थी। बाल सेवा योजना से मिली नियमित

आर्थिक सहायता और लैपटॉप ने उसकी शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया।' फतेहपुर के एक लाभार्थी युवा ने योजना के प्रभाव को साझा करते हुए कहा कि, 'एक समय ऐसा भी था जब लगने लगा था कि पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी। लेकिन सरकार की इस पहल ने अभिभावक की तरह मेरा साथ दिया। आज मैं डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा हूँ और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत कर रहा हूँ।'

वाराणसी की छात्रा और फतेहपुर के इस युवा की कहानी उन हजारों बच्चों और युवाओं के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की झलक है, जिनके लिए "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अवसर और सुरक्षित भविष्य की मजबूत आधारशिला बन चुकी है।

उम्मीदों को संबल, भविष्य को दिशा

जिन बच्चों ने कम उम्र में ही जीवन की सबसे बड़ी क्षति का सामना किया, उनके लिए "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" उम्मीद, संरक्षण और नए अवसरों का संबल बनकर सामने आई है। इसकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि नियमित आर्थिक सहायता है, जो बच्चों के जीवनयापन और शिक्षा को सहारा प्रदान करती है। दूसरी उपलब्धि शिक्षा के अधिकार को सशक्त बनाना है। निःशुल्क शिक्षा, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अभाव और विपरीत परिस्थितियाँ बच्चों की पढ़ाई में बाधा न बनें। तीसरी उल्लेखनीय उपलब्धि डिजिटल सशक्तीकरण है। लैपटॉप की उपलब्धता ने लाभार्थी बच्चों को आधुनिक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और नए अवसरों से जोड़ा है। चौथी उपलब्धि सम्मानजनक जीवन और गरिमा के अधिकार की रक्षा है। नियमित सहायता, बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग तथा सतत निगरानी व्यवस्था ने बच्चों को सुरक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान प्रदान किया है। पाँचवीं और सबसे व्यापक उपलब्धि बाल संरक्षण को मजबूत करना है। यह योजना बच्चों को बाल श्रम, शोषण, उपेक्षा और शिक्षा से वंचित होने जैसे जोखिमों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वास्तव में, "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" शासन की संवेदनशीलता का वह मानवीय स्वरूप है, जो बच्चों के वर्तमान को संवारते हुए उनके भविष्य को भी नई उड़ान दे रहा है। ◆

(लेखिका डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास वि.वि में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

मो. : 9205269749

प्रोजेक्ट गंगा से डिजिटली मजबूत होते गांव

—प्रदीप कुमार गुप्ता

सदियों से हमारे गाँव सभ्यता का केन्द्र रहे हैं। भारत को गाँवों का देश कहे जाने के पीछे भी यही तथ्य है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी कृषि, लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योग है। इनसे जुड़े अन्नदाता किसान, हस्तशिल्पी और कारीगर गाँव में रहकर अपने परिश्रम से न केवल देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते आ रहे हैं, बल्कि अपने हुनर से बने उत्पादों से देश व दुनिया के उद्यमियों, नागरिकों को आकर्षित भी करते रहे हैं। लेकिन विकास की तीव्र दौड़ में एक समय ऐसा भी आया, जब हमारे गाँव पीछे रह गए।

जैसे–जैसे आधुनिकीकरण व नगरीकरण होता गया और शहर अर्थव्यवस्था का केन्द्र बनने लगे, वैसे वैसे गाँव विकास की दौड़ में पिछड़ने लगे। जो कुछ कसर बाकी रह गई, वह नई तकनीक के शहरों और नगरों में केन्द्रण ने दूर कर दी। शहरों ने तकनीक को तेजी से अपनाया, जबकि हमारे गाँव इससे विमुख ही रहे। इसका कारण यह भी था कि जिस खेती और किसानी पर पूरी दुनिया टिकी हुई है और जिन गाँवों से भारत की पहचान है, वह कभी भी विकास के एजेण्डे में शामिल ही नहीं हो पाए। भूतपूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 'पुरा' (PURA) अर्थात, प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया की अवधारणा दी थी। इसका मतलब था कि गाँवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं देना। इनमें शहरों जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा तकनीक उपलब्ध कराने की बातें शामिल थीं।

विगत 09 वर्षों से भी अधिक समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने समृद्धि के नए आयाम प्राप्त किए हैं। अब विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गाँव भी विकास के केन्द्र बने हैं। प्रदेश के गाँवों में खेल के मैदान, ग्राम सचिवालय, हर घर जल योजना से शुद्ध पेयजल, सम्पर्क मार्गों का निर्माण, विद्यालयों में अनिवार्य रूप से मूलभूत सुविधाओं का विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। कृषि और किसानों के कल्याण की अनेक योजनाएं जैसे पी.एम. किसान आदि सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। अब हमारे गाँव भी विकास की दौड़ में कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम बने हैं।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने 09 जून, 2026 को प्रदेश के गाँवों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 'प्रोजेक्ट गंगा' का शुभारम्भ किया है। यह प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विकास की दृष्टि से देश में अपने तरह की पहली और अभिनव पहल है। 'प्रोजेक्ट गंगा'

(Government Assisted Network For Growth & Advancement) आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के क्रान्तिकारी परिवर्तनों का गवाह बनने जा रहा है। अब हमारे गाँव और वहां के नौजवानों सहित समाज का हर वर्ग न केवल तीव्र इण्टरनेट की सेवाएं प्राप्त करेंगे, बल्कि इसके माध्यम से स्वयं अपने और अपने परिवार की समृद्धि में भी सहयोग कर सकेंगे। अन्ततः यह उत्तर प्रदेश की समृद्धि को नए विस्तार और नए क्षितिज प्रदान करेगा।

'प्रोजेक्ट गंगा' उत्तर प्रदेश की डिजिटल अवसंरचना (विशेषकर ग्रामीण उत्तर प्रदेश की) को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार व प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह हिन्दुजा ग्रुप की साझेदारी में एक नई शुरुआत है। इसका लक्ष्य ग्रामीण उत्तर प्रदेश को हाई स्पीड ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी देना है, जिससे गाँवों में भी इण्टरनेट सेवाएं त्वरित, सर्वसुलभ और समावेशी बन सकेंगी। हिन्दुजा समूह की ब्रॉडबैण्ड इकाई One OTT Entertainment Limited परियोजना की नॉलेज पार्टनर तथा इम्प्लीमेण्टेशन एनैबलर के रूप में तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण एवं परिचालन सहयोग प्रदान कर रही है।

वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का है। सूचना क्रान्ति के इस दौर में, जहां प्रतिदिन एक नई तकनीक का आविष्कार हो रहा है, ऐसे में स्वयं को इससे अपडेट रखना अत्यन्त आवश्यक है। आर्टिफिशियल इण्टेलिजेंस, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स सहित अन्य सभी नवीन परिवर्तनों का आधार सूचना तकनीक में आ रहे तीव्र परिवर्तन ही हैं। अब कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी ने नई चुनौतियां उत्पन्न की हैं। साथ ही, इसके अनुरूप नए अवसर भी प्रदान किये हैं। 'प्रोजेक्ट गंगा' इन्हीं अवसरों को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज को सशक्त करने का माध्यम है। यह गाँवों में इण्टरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार ही नहीं, बल्कि समावेशी विकास, प्रदेश के निवासियों के डिजिटल सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का भी समयानुकूल माध्यम बनने जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन का परिणाम 'प्रोजेक्ट गंगा' के रूप में सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना विकसित करने के साथ-साथ यह बड़े पैमाने पर रोजगार एवं उद्यमिता सृजन हेतु भी एक महत्वपूर्ण पहल है। परियोजना के अन्तर्गत राज्य में 20 लाख से अधिक परिवारों को ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा प्रथम चरण में 8,000 से 10,000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) तैयार करने का लक्ष्य है। यह

डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर स्थानीय स्तर पर ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन वितरित करेंगे। स्थानीय युवाओं को उद्यमी बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। इस पहल से 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार तथा 01 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की सम्भावना है। प्रथम चरण में इसका 21 जनपदों में क्रियान्वयन किया जाएगा। इन जनपदों में मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, मथुरा, शाहजहांपुर, आगरा, बलरामपुर, लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी इसे शीघ्र ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों लगभग 57 हजार 700 ग्राम पंचायतों में विस्तार के लिए कृतसंकल्पित हैं।

डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर मॉडल के अन्तर्गत स्थानीय युवा अपने क्षेत्र में ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क स्थापित एवं संचालित करेंगे। इससे वे डिजिटल इण्टरप्रेन्योर के रूप में आत्मनिर्भर उद्यमी बनकर, ग्रामीण डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देंगे। प्रत्येक डी.एस.पी. अपने साथ ही, अनेक युवाओं को रोजगार देने में सक्षम बन सकेंगे।यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ई–गवर्नेंस, कौशल विकास तथा डिजिटल आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करेगी।

परियोजना में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हुए, लगभग 50 प्रतिशत महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण महिलाएं भी प्रदेश की उन्नति में भागीदार बन सकेंगी। हाल के वर्षों में बी.सी. सखी, ड्रोन दीदी जैसे सफल मॉडल से प्रदेश की अलग पहचान बनी है। अब 'इण्टरनेट दीदी' के रूप में प्रदेश की महिलाएं डिजिटल दुनिया के नए आसमान में नई उड़ान भरेंगी।

'प्रोजेक्ट गंगा' उत्तर प्रदेश को 'डिजिटल

एक्सप्रेस–वे प्रदेश' बनाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है। आज मोबाइल के दौर में जब दुनिया एक हथेली में सिमट गयी है, एक स्थान से सूचनाएं दूसरे स्थान तक पलक झपकते ही पहुंच जाती हैं। तब मुख्यमंत्री जी की पहल 'प्रोजेक्ट गंगा' उनके दूरगामी दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह स्पष्ट है कि आज वही समाज समृद्ध है, जिसकी सूचनाओं तक त्वरित और सुगम पहुँच है। इस रूप में 'प्रोजेक्ट गंगा' की उपयोगिता सर्वसिद्ध है। देश में संचालित एक्सप्रेस–वे नेटवर्क में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश 'एक्सप्रेस–वे प्रदेश' के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकार्पित 'गंगा एक्सप्रेस–वे' उत्तर प्रदेश की नई क्षमताओं का साकार रूप बना है। एक ओर जहां तीव्र सम्पर्क वाले एक्सप्रेस–वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन, व्यापार व पर्यटन सहित ईज ऑफ लिविंग को सुगम बनाते हैं। वहीं आज के युग में डिजिटल एक्सप्रेस–वे सूचना के आदान–प्रदान और तीव्र संचार का माध्यम हैं। फिजिकल एक्सप्रेस–वे की तरह यह भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

'प्रोजेक्ट गंगा' ग्रामीण क्षेत्रों में कम ब्रॉडबैण्ड पहुँच की समस्या का समाधान करते हुए शहरी–ग्रामीण डिजिटल अन्तर को समाप्त करने का प्रयास करती है। यह डिजिटल डिवाइड की समस्या का प्रभावी समाधान है। सामान्य मोबाइल इण्टरनेट के विपरीत, हाईस्पीड ब्रॉडबैण्ड डिजिटल शिक्षा, टेली–मेडिसिन, ए.आई. आधारित कृषि, वर्क फ्रॉम होम, ग्रामीण बी.पी.ओ. तथा स्मार्ट विलेज जैसी सेवाओं को सक्षम बनाता है।

'प्रोजेक्ट गंगा' ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार से लाभान्वित होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेज, डिजिटल लाइब्रेरी एवं स्किल डेवलपमेण्ट कोर्सेज तक युवाओं की आसान व त्वरित एक्सेस हो सकेगी। सुदूर ग्रामीण इलाकों में विद्यार्थियों को बेहतर लर्निंग अपॉर्च्युनिटी मिलने से वह भी अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकेंगे। प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की मदद होगी। वह ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग कर अच्छे शिक्षकों के कन्टेण्ट का लाभ ले सकते हैं। हर गाँव में मौजूद प्राथमिक विद्यालयों में हाल के वर्षों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। इनमें स्मार्ट क्लासेज जैसी पहलें भी शामिल हैं। अब हमारे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे तथा आंगनबाड़ी के नौनिहाल तकनीक के प्रयोग में न केवल सक्षम बनेंगे, बल्कि उन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने में भी शिक्षकों को आसानी होगी।

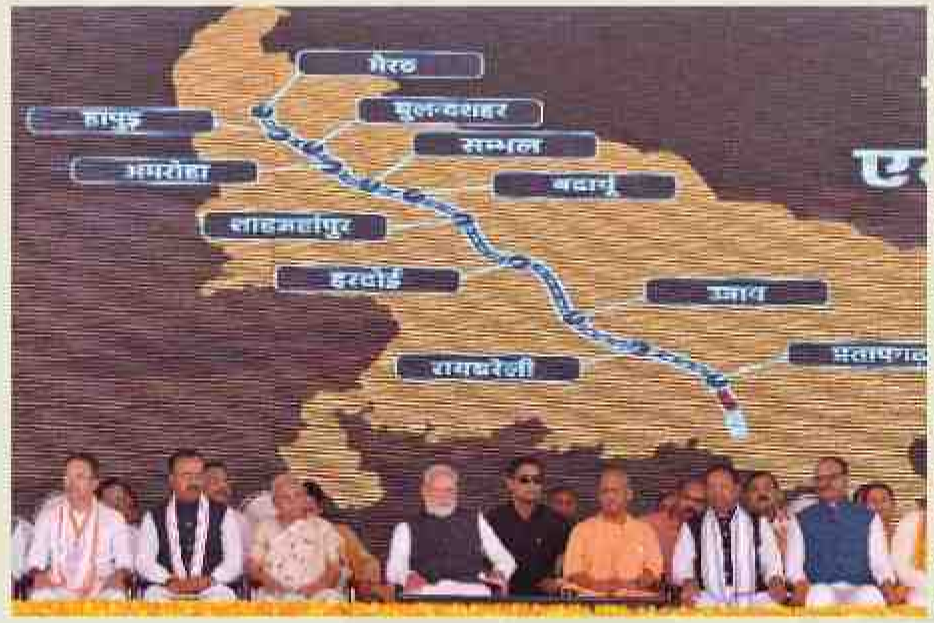

गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता का भी समाधान "प्रोजेक्ट गंगा' उपलब्ध कराता है। जब हाईस्पीड इण्टरनेट की सेवाएं उपलब्ध होंगी, तो टेली–मेडिसिन एवं स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। यह ऑनलाइन कन्सल्टेंसी को सर्वसुलभ बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हेल्थ इन्फॉर्मेशन तथा इमरजेंसी सर्विसेज तक लोगों की तेज एक्सेस होगी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से लोगों तक पहुँचेंगी। मातृ एवं शिशु सहित समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ेगी। सरकार इनका प्रभावी अनुश्रवण भी कर सकती है।

कृषि आज भी हमारे गाँव तथा पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। यह भी एक तथ्य है कि अभी हम अपनी कृषि क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कृषि से सम्बन्धित मौसम, बाजार मूल्य तथा क्रॉप एडवाइजरी से जुड़ी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने से किसानों का कार्य आसान हो सकेगा। ऑटोनॉमस सिंचाई प्रणाली तथा ऑटोनॉमस इक्विपमेण्ट्स का प्रयोग कर किसान अपनी कृषि को लाभदायी बना सकेंगे। अभी हमारी कृषि में आधुनिक तकनीकों का उतना प्रयोग नहीं होता, जितना अन्य देशों में होता है। परिणामस्वरूप हमारे यहां खेती में लागत ज्यादा तथा उत्पादकता कम होती है। आधुनिक कृषि तकनीक का आधार उच्चगति संचार सेवाएं ही हैं। हर आधुनिक उपकरण इण्टरनेट से जुड़ा है। ऐसे में उनकी उपयोग तेज गति इण्टरनेट सेवाओं पर ही निर्भर है। इस दृष्टि से 'प्रोजेक्ट गंगा' की उपयोगिता समझना आसान हो जाता है।

गाँव में रोजगार की गुणवत्ता की एक समस्या होती है। ऐसे में अक्सर ग्रामीण युवा थोड़ी–बहुत शिक्षा अर्जित कर शहरों में पलायन कर जाते हैं, जहां के तेज गति से दौड़ते वातावरण में समायोजन करना आसान नहीं होता। 'प्रोजेक्ट गंगा' में गाँवों से होने वाले पलायन का समाधान भी छिपा है। यह रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देकर गाँवों में रिमोट वर्क, वर्क फ्रॉम होम तथा डिजिटल बिजनेस की संस्कृति को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे गाँव के युवा को गाँव में ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं अपने रोजगार से सम्बन्धित कार्यों को करते हुए ही घर–परिवार में भी अपनी सार्थक भूमिका

विगत नौ साल से भी अधिक समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने समृद्धि के नए आयाम प्राप्त किए हैं। अब विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गाँव भी विकास के केन्द्र बने हैं। प्रदेश के गाँवों में खेल के मैदान, ग्राम सचिवालय, हर घर जल योजना से शुद्ध पेयजल, सम्पर्क मार्गों का निर्माण, विद्यालयों में अनिवार्य रूप से मूलभूत सुविधाओं का विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। कृषि और किसानों के कल्याण की अनेक योजनाएं जैसे पी.एम. किसान आदि सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। अब हमारे गाँव भी विकास की दौड़ में कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम बने हैं।

निभा सकते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से पारम्परिक परिवार की अवधारणा को संरक्षित करने में योगदान देगा। ग्रामीण बी0पी0ओ0 एवं डिजिटल सर्विस सेण्टर स्थापित होंगे, जिसका आधार ही तेज गति इण्टरनेट सेवाएं हैं।

'प्रोजेक्ट गंगा' शासकीय ऑनलाइन सर्विसेज जैसे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, कल्याणकारी योजनाओं तक जरूरतमन्दों की आसान पहुँच सुनिश्चित करता है। यह वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल पेमेण्ट, ऑनलाइन बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता जैसे कार्यों को बढ़ावा देकर गाँवों में 'सरकार आपके द्वार' की अवधारणा को साकार करता है। जिन कार्यों के लिए अक्सर ग्रामीणजन को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अब वह सारे प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में ही सर्वसुलभ होंगे। प्रदेश सरकार ने हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय के रूप में ग्राम प्रधान तथा लेखपाल जैसे सरकारी सेवकों के लिए स्थायी कार्यालय की सुविधा दी है। ग्राम सचिवालय की यह पहल नीति आयोग द्वारा सराही गयी है। अब इन सचिवालयों में भी तीव्र गति ब्रॉडबैण्ड की इण्टरनेट सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे यह और भी प्रभावी रूप से अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

हर बिजनेस की शुरुआत किसी नए आइडिया से होती है। ग्रामीण युवाओं में कर्मठता तथा मेहनत करने का जज्बा होता है। वह भी ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ऐसे में तकनीक उन्हें नई बिजनेस अपॉर्च्युनिटी दे सकती है। जिससे अन्ततः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोडक्टिविटी तथा इनकम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। 'प्रोजेक्ट गंगा' से नए–नए बिजनेस आइडिया तथा नवाचारों तक ग्रामीण युवाओं एवं उद्यमियों की पहुंच बढ़ेगी। यह सोशल कम्युनिटी को बढ़ाकर लोगों को अपने परिवार तथा समाज से जुड़ने में मदद करेगा। देश और दुनिया से जुड़े समाचार, सूचना एवं मनोरंजन तक पहुंच आसान हो जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने 'विरासत भी, विकास भी' के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए समृद्धि के नए शिखर को छुने में सफलता प्राप्त की है। गाँव, जिनसे भारत की पहचान है, अब वह भी तेजी से विकास की मुख्यधारा से जोड़े जा रहे हैं। 'प्रोजेक्ट गंगा' मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील दूरदृष्टि का प्रतिफल है। प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर और विकसित भारत' के संकल्प की सिद्धि का रास्ता उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के गाँवों के विकास से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में हमारे गाँव व ग्रामीणजन भी अपना योगदान कर सकें, इस दृष्टि से 'प्रोजेक्ट गंगा' एक नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में नवीन अवसर लेकर उपस्थित है। ग्रामीण युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए संकल्पित 'प्रोजेक्ट गंगा' ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी हेतु सक्षम बनाती है। उत्तर प्रदेश के गाँवों में डिजिटल सशक्तिकरण की नई गंगा बहने को तैयार है। आप भी इस यात्रा के भागीदार बनिए। ◆

(लेखक मुख्यमंत्री सूचना परिसर में
फीचर लेखक/सूचना अधिकारी हैं)
मो. : 7705800992

विकास की नयी उड़ान भरता गोरखपुर

–रुद्रेश घिल्डियाल

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात गोरखपुर ने विकास की नई गाथा लिखी है। पूर्वान्चल के हृदय में स्थिता यह जनपद अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और अधोसंरचना के क्षेत्र में नये–नये मानक स्थापित कर रहा है। एम्स गोरखपुर के आरम्भ से लेकर बन्द पडी खाद फैक्ट्री के पुनर्जीवन तक, हर कदम पर सरकार ने जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता दी है। रामगढ़ ताल का कायाकल्प, हवाई अड्डे का विस्तार और सुदृढ़ सड़क सम्पर्क ने न केवल शहर की सुन्दरता–दिव्यता बढ़ाई है, बल्कि व्यापार और रोजगार को भी नई गतिमान स्थापित की है। रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण ने यात्रा सुविधाओं को और युवा अवसरों का उभरता हुआ केन्द्र बन चुका है। यह परिवर्तन जनता के सहयोग, मजबूत इच्छाशक्ति और पारदर्शी शासन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश के सी.एम. योगी का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध जीवन जी सके। गोरखपुर की ये सफलतायें "समृद्ध प्रदेश विकसित भारत" के संकल्प को और मजबूत करती है। गोरखपुर मण्डल में योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र का हर वादा पूरा किया है। अपने 9 वर्ष के शासनकाल में योगी सरकार ने गोरखपुर मण्डल में सिर्फ लोगों से किया अपना वादा ही पूरा नहीं किया है बल्कि गोरखपुर के अन्तिम व्यक्ति तक की नजर में मुख्यमंत्री की अलग छवि है। योगी के प्रति अपार श्रद्धावश कोई उन्हें मसीहा कहता है तो कोई साक्षात भगवान का रूप मानता है। आजादी के अमृत काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्वान्चल औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का ऐतिहासिक फैसला लेकर गोरखपुर मण्डल (पूर्वान्चल) के सर्वांगीण विकास की पहल की है। पूर्व की सरकारों में बदहाल पूर्वान्चल अब डबल इंजन की सरकार में विकास के बुलन्दी की गाथा लिख रहा है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उ.प्र. सरकार पूर्वान्चल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र की प्रगति के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गोरखपुर में एम्स खुलने से पूर्वान्चल में उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवायें आसानी से उपलब्ध हुई। इससे नेपाल व बिहार से आने वालों को भी राहत मिली

है। पहले जो मरीज इलाज के लिए दिल्ली, लखनऊ जाते थे, अब वही उपचार गोरखपुर में भी सम्भव हुआ है। यही नहीं कभी गन्दगी से भरा ताल अब शानदार लेकफ्रंट, बोरिंग फॉर एडवेन्चर स्पोर्ट्स का केन्द्र बन चुका है। अब स्थानीय व्यापार को बड़ी बढ़त और शहर को नयी पहचान मिली है।

आज गोरखपुर हवाई अड्डे से बड़ी रफ्तार के कारण अर्न्तराष्ट्रीय मानकों पर बने नए टर्मिनल से हवाई यात्राओं में वृद्धि के साथ व्यापार, पर्यटन और ट्रैवल में तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि नई इबारत लिखी जा रही है साथ ही नई ऊंचाइयां स्थापित की जा रही हैं। गोरखपुर मण्डल के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के मार्गदर्शन में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का मेक ओवर भारतीय रेल का माडल जंक्शन का रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया हैं। स्वच्छता, सुरक्षा और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक इन्तजाम भी किया गया है।

योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपने 9 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत के तत्त्वों को युवा मन में बिठाने के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है। शिक्षा का स्टार्टअप में नया उभार युवाशक्ति की नयी उड़ान, नये शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी कॉलेज और स्किल डेवलपमेन्ट केन्द्र स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा, युवाओं के लिए नये अवसर दिये गये हैं, यही नहीं उच्च शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिहाज से अव्वल बना दिया है।

गोरखपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार आदर्श बना गोरखपुर जिसमें मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल और पी.एच.सी. में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं जिसमें मातृ शिशु मृत्यु दर में गिरावट, टीकाकरण अभियान सफल साबित हुआ है।

योगी सरकार द्वारा गोरखपुर मण्डल में निवेश और

उद्योग बढ़े हैं जिसके कारण पूर्वान्चल के औद्योगिक क्षेत्र ग्रीन फील्ड पार्क, एम.एस.एम.ई. कलस्टर और नयी औद्योगिक यूनिटस स्थापित की गयी हैं जिसमें गोरखपुर के युवाओं के लिए रोजगार सृजन के नये अवसर दिये गये हैं। योगी सरकारी द्वारा पूर्वान्चल में लेन, सड़कें व नयी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना कनेक्टीविटी का सुपर अपग्रेड अन्तर्गत गोरखपुर–लखनऊ, गोरखपुर–वाराणसी और अन्य मार्गों का सुन्दरीकरण किया गया है जिसमें यात्रा समय कम, व्यापार और उद्योग का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। इसी के साथ फर्टिलाइजर फैक्ट्री का पुनर्जीवन रोजगार और उत्पादन का नया युग शुरू किया गया है। कई सालों से बन्द पडी उर्वरक फैक्ट्री फिर से शुरू की गई। हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है। महायोगी गुरू गोरखनाथ की पावन नगर निगम गोरखपुर में महाराणा प्रताप इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी में टाटा समूह के सहयोग से संचालित सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर–कमलों द्वारा किया गया है। गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर क्षेत्र में रू. 3 करोड़ से पाण्डेय दाता में व्यवसायिक काम्पलेक्स हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास एवं रू.29 करोड़ से ऐतिहासिक घंटाघर के जीर्णोद्धार कार्य शहीद बन्धु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग और व्यवसायिक भवन का लोकार्पण का माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया है, जिसमें पूर्वान्चल के गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। आज गोरखनाथ मन्दिर क्षेत्र का विकास आस्था व संस्कृति को सम्मान के साथ मन्दिर परिसर में सुविधाओं का विस्तार और सुरक्षित व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था के तीर्थ पर्यटन में रिकार्ड वृद्धि निरन्तर जारी है।

गोरखपुर क्षेत्र में वनटांगियों समुदाय के लोगों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनके संसदीय कार्यकाल से ही विशेष लगाव रहा है। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक तो उन्होंने वनटांगियों की बदहाली दूर करने के लिए निजी तौर पर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की, जिसका प्रासंगिक विवरण इस प्रकार से है कि जंगल तिकोनिया नम्बर, नम्बर तीन निवासी सुभावती बताती हैं कि बाबा की नजर यहाँ पड़ने से पहले ''मड़ई'' में ढिबरी जलाकर रहना पड़ता था। वह मुख्यमंत्री बने तो सबका पक्का मकान बन गया, घर–घर बिजली है, सबके पास रसोई गैस है और 35–40 किलो राशन भी मिलता है। अपने शब्दों में बाबा जी को भगवान का दूसरा रूप बताते हुए सुभावती यह कामना करती हैं कि वह ही बार–बार मुख्यमंत्री बनें। इसी गांव की बुजुर्ग पतिरजी देवी बताती हैं कि पहले हमलोग मजदूर थे, बाबाजी ने खेत का अधिकार देकर जमीन का मालिक बना दिया। भावुक होकर वह कहती हैं कि जंगल के हमारे गांव में बाबा जी भगवान बनकर आए। उन्होंने इतना कुछ दिया कि यहाँ रामराज्य ला दिया। वनटांगियों की बस्ती में योगी आदित्यनाथ की पहल पर खुले स्कूल हिन्दू विद्यापीठ में वर्ष 2007 से शिक्षण कार्य करने वाले संजय गुप्ता का कहना है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गांव का कायाकल्प हो गया है। टूटी–फूटी मड़ई वाले गांव में शहरी स्तर का विकास कभी–कभी अकल्पनीय लगता है, यह सौ फीसदी हकीकत है।

वनटांगियाँ गांव का इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है। 1918 के आस–पास इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने साखू के जंगल लगाने के लिए बसाया था। सौ सालों से अधिक समय तक यह राजस्व अभिलेखों में नागरिक के दर्जे से भी वंचित थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इन वनग्रामों को राजस्व अभिलेखों में शामिल किया। आज वनटांगिया गांवों में हर परिवार के पास प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास

योजना के तहत पक्के मकान हैं। सभी घरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय है, सबके पास राशन कार्ड है, उज्जवला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क रसोई गैस की सुविधा है तथा सौभाग्य योजना के निःशुल्क विद्युत कनेक्शन से उनके घर रोशन हैं। इन गांवों में लोग पात्रता के अनुसार पेंशन योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कभी शिक्षा इनके लिए दूर की कौड़ी थी, अब इनके गांव में ही सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्र बन चुके हैं। गांव के लोग आर.ओ. मशीन से शुद्ध पेयजल प्राप्त करते हैं। यह सब कुछ हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफल मार्गदर्शन में। ♦

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
मो. : 9453059581

विकास के केंद्र में बुद्ध की क्रीड़ास्थली

–रवि प्रकाश

पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की पहचान गौतम बुद्ध से है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तीन दशक पूर्व बस्ती जिले के उत्तर स्थित नौगढ़ तहसील को अलग कर राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर सिद्धार्थनगर जिले का सृजन हुआ है। लंबी खुदाई के बाद जिला मुख्यालय से बीस किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित पिपरहवा नामक स्थान को गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन की राजधानी के रूप में चिह्नित किया गया। यहां के स्तूप और अवशेष प्राचीन कालीन राजमहल के खंडहर जैसे लगते हैं। वे आज भी विद्यमान हैं। पिपरहवा को ही कपिलवस्तु कहा गया है। राजा शुद्धोधन की राजधानी का नाम कपिलवस्तु ही था। यहां 29 वर्ष तक गौतम बुद्ध का जीवन व्यतीत हुआ है। इस नाते कपिलवस्तु को गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है।

बुद्ध के इस महत्वपूर्ण स्थल तक श्री लंका के राष्ट्रपति सहित बुद्ध को मानने वाले देशों के बुद्धिष्ट आते रहे हैं। 80–90 के दशक में यहां विदेशी बुद्ध अनुयायियों का आना जाना लगा रहता था। उनके लिए स्पेशल ट्रेन की बोगी आती थी जो यहां रेलवे स्टेशन पर दो चार दिन रुकती

थी। फिर उन्हें लेकर वापस जाती थी।

कपिलवस्तु महोत्सव शुरू

यह स्थल अंग्रेजों के लिए भी खास था लेकिन उनकी नीयत में खोट थी। पिपरहवा की खुदाई में मिले बुद्धकालीन अवशेष जो खास थे, उसे तत्कालीन अंग्रेज जमींदार विलियंस पेपे लंदन लेते गए। मई 2025 में उस अवशेष की नीलामी हांगकांग में होने वाली थी। सिद्धार्थनगर के निवासी पूर्व डीजीपी बृजलाल जो इस समय राज्य सभा के सांसद हैं, उन्होंने खत लिखकर इस ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ध्यान आकृष्ट कराया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भारत सरकार और गोदरेज ग्रुप के प्रयास से हांगकांग से बुद्ध के खास अवशेष भारत लाए जा सके। इसे लेने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक प्रतिनिधि मंडल हांगकांग गया था। बुद्ध अवशेष दिल्ली में राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में स्थित म्युजिअम में रखे गए हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां एक उद्घाटन समारोह में पिपरहवा के माहात्म्य की चर्चा खास तौर पर की।

पिपरहवा के खंडहरनुमा स्तूप को संरक्षित कर इसी के समीप सौ एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर कपिलवस्तु के विकास की तमाम योजनाएं बनीं जरूर लेकिन राजनीतिक कारणों से यह मूर्त रूप नहीं ले पाई। सच कहा जाए तो यहां जो भी विकास के कार्य हुए, वह भाजपा सरकारों के समय ही हुए। वह चाहे स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह का कार्यकाल रहा हो या राजनाथ सिंह का। स्थानीय स्तर पर यदि इसके विकास के बारे में किसी ने सोचा तो वह स्वर्गीय धनराज यादव रहे हैं जो भाजपा के कई बार के विधायक और मंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का सपना है कि पिपरहवा (कपिलवस्तु) का विकास अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप कुछ यूं हो कि यह विदेशी मुद्रा के स्रोत का बड़ा हिस्सा भी बने।

गौतम बुद्ध एक तरह के योगी ही थे। उनके विभिन्न योग मुद्राओं का वर्णन बुद्ध कालीन इतिहास में मिलता है। वे चिंतन, मनन, मौन हर वक्त अलग-अलग मुद्रा में होते थे। दुनिया में खास तौर पर बुद्ध को मानने वाले देशों में सिद्धार्थनगर जिले की शिनाख्त बुद्धमय जिले के रूप में हो, इसके लिए जिले की चारों सीमाओं पर गौतमबुद्ध की खास योग मुद्राओं के स्टैच्यू की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं योग साधना वाले संत हैं। उनकी मंशा के अनुरूप ही जिले के चारों सीमाओं पर बुद्ध की योग मुद्राओं

और जापान के दौरे पर थे। योगी के इस दौरे का उद्देश्य यूपी को आर्थिक मजबूती देने के लिए दोनों देशों से निवेश की दरकार की थी, इस यात्रा में बुद्ध से बौद्ध तक के आत्मीय रिश्ते की डोर को मजबूत करना भी योगी की बड़ी कामयाबी रही।

बता दें कि बौद्ध तीर्थ स्थलों की दृष्टि से यूपी का खास महत्व है। यहां शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु (पिपरहवा) के अलावा सारनाथ श्रावस्ती, देवदह, कुशीनगर आदि बौद्ध स्थल मौजूद हैं। इन सभी स्थलों के अपने–अपने

की स्थापना की गई। जिले के दो नगरपालिका और नौ जिला पंचायतों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की सीमाओं पर इस योग मुद्रा की स्थापना कराई गई है।

कपिलवस्तु के विकास के बारे में पूर्व की गैर भाजपा सरकारों ने सिर्फ योजनाएं बनाईं, क्रियान्वयन नहीं किया। अब योजनाएं बनने के साथ काम भी हो रहा है। यही वजह है कि इस जिले की बुद्ध मयता की पहचान वापस आ रही है। यह सब मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल, यहां के जनप्रतिनिधियों की रुचि और जिला प्रशासन की तत्परता से संभव हो पा रहा है। कपिलवस्तु के विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देकर इसे बौद्ध देशों के आकर्षण के केन्द्र के रूप में स्थापित करना है। कपिलवस्तु से कुछ दूर पर ही नेपाल के लुंबिनी को बौद्ध देशों ने अरबों खर्च कर विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, इसलिए कि वह बुद्ध की जन्मस्थली है लेकिन यदि हम कपिलवस्तु को थोड़ा भी आकर्षक बना पाए तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यहां भी बौद्ध देशों की नजर ए इनायत होगी और यूपी की शिनाख्त जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा वाले प्रदेश की है, उसमें एक नाम सिद्धार्थनगर भी जुड़ जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले महीने सिंगापुर

महत्व है। जापान की राजधानी टोकियो में योगी आदित्यनाथ ने इन सभी बौद्ध स्थलों के बारे में विस्तार से वर्णन कर जापान और सिंगापुर के शासकों का ध्यान यूपी के बौद्ध स्थलों की ओर खींचा। योगी ने सिंगापुर और जापान में उद्योग पतियों, बड़े व्यवसायियों और निवेशकों की मीटिंग में भारत और खासकर यूपी के प्रमुख बौद्ध स्थलों के महत्व को बताते हुए भारत से सिंगापुर और जापान से धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी रेखांकित किया।

बौद्ध अनुयायियों की दृष्टि से जापान और सिंगापुर बड़ी आबादी वाला देश है।

मुख्यमंत्री ने सिंगापुर और जापान दोनों देशों में पर्यटन विकास की बात कर यूपी के बुद्ध स्थलों की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया। उम्मीद की जानी की चाहिए देर–सवेर जब भी यूपी के बौद्ध स्थलों की ओर सिंगापुर और जापान की नजरें इनायत हुई तो निश्चित ही इसकी शुरुआत कपिलवस्तु से होगी। ◆

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
मो. : 8303851539

जेवर से वैश्विक उड़ान, बदलते यूपी की पहचान

–अशोक सिंह

जमीन से आसमान तो सभी देखते हैं लेकिन आसमान से जमीन देखने का सुख भाग्यशाली लोगों को ही नसीब होता है। जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद किया। एयरपोर्ट निर्माण के लिए उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने भी इंडिगो की पहली उड़ान से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे किसानों का तहे दिल से स्वागत किया। मुख्यमंत्री से संवाद में किसानों ने कई दिल छू लेने वाली बातें भी कहीं। मसलन, वे आसमान में विमानों को उड़ते हुए देखा करते थे लेकिन विमान में बैठने और आसमान से अपनी जमीन और अपना घर देखने का सुख उन्हें पहली बार मिला है। योगी आदित्यनाथ ने सही मायने में चप्पल पहनने वालों को विमान में बैठाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा पूरा कर दिया है। ये उद्गार सरकार की विकास नीति पर जनता की मुहर नहीं तो और क्या हैं?

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई–अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है और इसी के साथ विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के खाते में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। इंडिगो ने जेवर से हवाई सेवाओं का श्रीगणेश कर दिया है। लखनऊ से आई उद्घाटन उड़ान के स्वागत के बाद बेंगलुरु के लिए पहली प्रस्थान उड़ान की रवानगी केवल एक नए हवाई अड्डे की शुरुआत नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की एक बड़ी पहल है जो बेहद स्वागत योग्य है। जेवर स्थित इस विश्वस्तरीय हवाई अड्डे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लाखों लोग सुविधाजनक हवाई सफर का आनंद ले सकेंगे। इससे

पर्यटन, निवेश और व्यापार में इजाफा होगा। स्थानीय युवकों को भी रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे।

रही बात नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण के विकास की तो वह हुआ ही इस लिहाज से है कि हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री यहां से उड़ान भर सकें। भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष तक करने की केंद्र और राज्य सरकार की योजना है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजिटल यात्रा प्रणाली विकसित की जा रही है जिससे यात्रियों को भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता कम पड़े। सेल्फ चेक–इन, सेल्फ बैग ड्रॉप, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा सहज मार्गदर्शक प्रणालियां यात्रा को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन कुछ इस तरह तैयार किया गया है जिससे आधुनिक तकनीक और भारतीय सांस्कृतिक विरासत की झलक विमान यात्रियों को मिल सके और वे अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकें। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को दर्शातीं कलाकृतियां, वाराणसी के घाटों से प्रेरित स्थापत्य शैली, जालीदार डिजाइन तथा प्राकृतिक प्रकाश का संयोजन यात्रियों को एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट टैक्सी, ऐप आधारित कैब सेवाएं और दिल्ली–एनसीआर सहित उत्तर भारत के विभिन्न शहरों को जोड़ने वाली बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भावी समय में यह हवाई अड्डा वैश्विक संपर्क का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। हवाई अड्डे पर एयर इंडिया सैट्स द्वारा विकसित आधुनिक कार्गो सुविधाएं प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष दो लाख मीट्रिक टन माल ढुलाई की क्षमता रखती हैं, जिसे भविष्य में 15 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे ई–कॉमर्स, कृषि उत्पादों के निर्यात और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु की मानें तो नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू होना भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह हवाई अड्डा हवाई संपर्क को नई मजबूती देगा। व्यापार, पर्यटन, निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा

संवाद किया। विकास, कानून–व्यवस्था पर खुलकर अपनी बात रखी। यहां तक कह दिया कि यह बाबाजी का राज है, जेवर में आज किसी की हिम्मत नहीं कि किसान या आमजन से पैसे छीन ले। हज से लौटे एक बुजुर्ग किसान ने एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और कुछ बड़े प्रोजेक्ट को जेवर की नई पहचान करार दिया।पहली बार हवाई जहाज में बैठकर लखनऊ पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री से कहा कि जिस जमीन पर कभी वे खेती करते थे, आज उसी जमीन से उड़ान भरते विमान उत्तर प्रदेश के बदलते भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को बदल दिया है। किसान हंसराज ने की मानें तो उनके साथ लखनऊ आए ज्यादातर किसानों की यह पहली विमान यात्रा थी। किसान जयवीर सिंह ने प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री के अथक प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना की। यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सीएम योगी का सपना साकार हो रहा है। जेवर के एक किसान की बेटी डॉ. हिरा राशिद ने तो यहां तक कह दिया कि अगर योगी जी सीएम नहीं होते तो शायद एमबीबीएस डॉक्टर बनने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होता। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिता अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भरकर मैं मुख्यमंत्री से मिलने आई हूं। इस अवसर पर किसानों कमलेश देवी, पूनम देवी, कनिष्क, बबली देवी और मधु देवी ने मुख्यमंत्री को राधा–कृष्ण की प्रतिमा, मनवीर सिंह खटीक, बलभद्र, वेद प्रकाश शर्मा, पूरन सिंह कोरी, हजारी बघेल, खड़ेश्वर तथा महिपाल सिंह जाटव ने मुख्यमंत्री को किसान की उड़ान लिखा स्मृति चिह्न भेंट किया। किसान हाजी जफर ने तो लगभग दिल छू लेने वाली बात कह दी। उनके मुताबिक, सरकार ने ऐसा काम किया है कि हवाई चप्पल पहनने वाले किसानों को हवाई जहाज में बैठा दिया। भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों ने खुशी–खुशी अपनी जमीन दी। आज उन्हें जेवर में हुए इस विकास कार्य पर गर्व है। जिस एयरपोर्ट के लिए उनकी जमीन गई थी और आज उसी एयरपोर्ट से उड़ान भरकर राजधानी पहुंचना उनके लिए गर्व का विषय है। सरकार ने किसानों को केवल मुआवजा ही नहीं दिया बल्कि उन्हें विकास यात्रा का सहभागी भी बनाया है। किसान सुमन ने बताया कि उन्होंने जीवन में पहली बार हवाई जहाज में सफर किया है। यह उनका वर्षों पुराना सपना था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। मीनू ने भी कहा कि एयरपोर्ट बनने के बाद पहली बार उन्होंने अपनी जमीन को आसमान से देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ संवाद करते हुए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत को जेवर, गौतमबुद्ध नगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के विमानन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पल करार दिया।

गौरतलब है कि चार चरणों में अधिग्रहीत की गई 1,300 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय

हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है। अब जेवर दिल्ली को मात देने जा रहा है। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति आज वहां जाना चाहता है। अब तो धन के देवता कुबेर भी वहां जाना चाहते हैं। बकौल मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के किसान अब नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विकसित की जा रही कार्गो सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। फलों, सब्जियों, अनाज और मत्स्य उत्पादों सहित अन्य उपज को वैश्विक बाजारों में पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

वाली इन महिलाओं ने प्रदेश में बढ़ते महिला सशक्तीकरण और समान भागीदारी का उदाहरण पेश किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और संवेदनशीलता का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें किसान केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास के सम्मानित साझीदार बनकर उभरे हैं। जिन पैरों में कभी खेत की मिट्टी लगा करती थी, आज वही विमान जब विमान की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो उनकी प्रसन्नता और रोमांच का

यह कहने में शायद ही किसी को कोई हिचक हो कि उत्तर प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक ऐतिहासिक और भावनात्मक अध्याय जुड़ गया है। जेवर क्षेत्र के किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए यह सुखद अवसर रहा कि हवाई यात्रा के प्रतिनिधिमंडल में 20 महिला किसान भी शामिल रहीं। ग्रामीण परिवेश से निकलकर पहली बार विमान यात्रा करने

आलम क्या रहा होगा,इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। यह विमान यात्रा CI दरअसल किसानों के आत्मसम्मान के उत्सव से कम नहीं रही। यह सरकार के प्रति किसानों के उस विश्वास का परिणाम है, जिसने प्रदेश की तस्वीर बदलने में मील के पत्थर की भूमिका अदा की है। ◆

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

मो. : 8175880121

प्राथमिकता पर प्राथमिक शिक्षा

–रजनीश वैश्य

मजबूत राष्ट्र निर्माण में बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका है। जितनी मजबूत शिक्षा की नींव होगी, उतना ही मजबूत देश बनेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन के लिए काफी कार्य किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में पिछले 9 साल में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों की रंगत बदल चुकी है। विद्यालय एक ओर नौनिहालों से गुलजार रहता है तो अवस्थापना सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षकों और शिक्षामित्रों के हितों को भी पूरा किया जा रहा है।

किसी भी विद्यालय में शिक्षकों व अन्य मानव संसाधन का अभाव न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। नए अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश के नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11508 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी। आकांक्षात्मक जनपदों में संचालित सभी शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता के साथ पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। मानक अनुरूप विद्यालयों में शिक्षक–छात्र अनुपात रखने पर जोर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार के उद्देश्य से 'पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना की घोषणा की गई है। योजना अंतर्गत से प्रदेश के 1722 विद्यालय आच्छादित हैं। पीएम श्री के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप चरणबद्ध रूप से इन विद्यालयों में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकी व डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जा रहा है। इन

विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, लैंग्वेज लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जा रहे हैं। सोलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, ऊर्जा कुशल संसाधन, पोषण वाटिका, वेस्ट मैनेजमेंट, जल संरक्षण आदि के माध्यम से इन्हें ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट प्रशिक्षित शिक्षक

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम तथा आईसीटी लैब की स्थापना की जा रही है। यहां छात्रों को कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा में गुणवत्ता हेतु शिक्षकों को 2.61 लाख टैबलेट वितरित किए गए हैं। विद्यालयों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जा रही है।

प्रदेश के 15,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में परिवर्तित किया गया है। अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल प्रदेश के हर ब्लॉक में संचालित किए जाएंगे।

निपुण भारत के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं कक्षाओं के उच्चीकरण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। वर्ष 2025–26 में 4.33 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षक कार्यशाला एवं यूट्यूब लाइव के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे शिक्षा के स्तर में और बढ़ोतरी कर सकें। गुरुजनों का सम्मान सरकार की परम्परा रही है। इस क्रम में राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गयी है।

शिक्षामित्रों को उपहार

पिछली सरकारों के उदासीन रवैये के कारण करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों के परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। वर्षों से सेवा दे रहे इन शिक्षामित्रों की सेवाएं समाप्त होने के कगार पर थी। योगी सरकार ने साहसिक निर्णय लिया कि उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएगी, बल्कि शिक्षा कार्य में उनका सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका मानदेय बढ़ाने का भी कार्य किया गया। वर्ष 2017 से पूर्व उन्हें नाम मात्र का मानदेय मिलता था। वर्ष 2017 के बाद मानदेय ₹3,500 से बढ़ाकर ₹10,000 किया गया। अब उन्हें ₹10 हजार से बढ़ाकर ₹18 हजार प्रतिमाह किया गया है। इसका लाभ बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त 1 लाख 43 हजार शिक्षामित्रों को मिलेगा।

इसके साथ ही शिक्षामित्रों को बीमा का लाभ भी मिलेगा, जिससे अनहोनी की दशा में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को ₹5 लाख वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने की व्यवस्था भी की है। शिक्षण कार्य में उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिक्षामित्रों की तैनाती उनके जिले के नजदीकी विद्यालयों में करने की व्यवस्था की गयी है। विवाहित महिला

शिक्षामित्रों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प रखा गया है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय भी दोगुना करते हुए 17 हजार रुपए कर दिया गया है। इससे पूर्व अनुदेशकों को 8,470 रुपए का मानदेय मिलता था।

हर बच्चे के लिए स्कूल

सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। शिक्षा सत्र में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाता है। वर्तमान में प्रथम चरण में 20 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया है तथा आगामी समय में और अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक समय था, मूलभूत शिक्षा व्यवस्था के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। पिछले 9 वर्षों में शिक्षा की दिशा में आधारभूत सुधार हुआ है। इसका परिणाम है कि ड्रॉप आउट रेट 19 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गया है। सरकार का लक्ष्य इसे शून्य तक लाना है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2024–25 में 13.22 लाख तथा 2025–26 में 15.84 लाख बच्चों का नामांकन किया गया है। आउट ऑफ स्कूली बच्चों के लिए शारदा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बच्चों के चिन्हांकन व नामांकन हेतु सघन हाउस होल्ड सर्वे पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। असेवित क्षेत्रों, मलिन बस्तियों, झुग्गी–झोपड़ी, ईंट–भट्ठों, कारखानों एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत परिवारों के बच्चों व जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा जा रहा है।

निःशुल्क सुविधाओं से सुधरी शिक्षा व्यवस्था

एक समय में प्राथमिक स्कूल के बच्चे घर के कपड़ों में ही स्कूल चले आते थे। कपड़े फटे पुराने भी रहते थे। जूता–मोजा पहन कर आने की बात ही छोड़ दें, हवाई चप्पल या नंगे पैर ही स्कूल आ जाते थे। किताबें हाथों में या पन्नी में लेकर आना नौनिहालों के नसीब में था। जाड़े में गर्म कपड़ों के अभाव में वे ठिठुरते हुए आते थे, घर पर जाड़ा ही मानते रह जाते थे। इससे उनकी शिक्षा पिछड़ रही थी। अनुशासन भी नहीं बन पा रहा था। योगी सरकार ने बच्चों के इस दर्द को समझा। सरकार ने 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते, मोजे और स्वेटर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली, जिससे बच्चे पूरे शान के साथ आराम से पढ़ सकें। प्रति छात्र 1200 रुपये की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इस राशि से उनकी यूनिफॉर्म और स्कूल बैग जैसे मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाती हैं। कक्षा 1–8 तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व कार्य पुस्तिकाएं प्रदान की जाती है।

स्कूलों का कायाकल्प

जर्जर स्कूलों की जगह अब प्राथमिक विद्यालय स्मार्ट क्लास से सुसज्जित नजर आते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है। विद्यालयों में टॉयलेट, पेयजल, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं। इससे सरकारी स्कूल महंगे निजी स्कूलों को टक्कर देते

नजर आते हैं। सुविधाओं के विस्तार होने के बाद प्रति वर्ष स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में भी विस्तार हो रहा है। सरकार के प्रयासों से विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता 30–36 प्रतिशत से बढ़कर 96–99 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

शिक्षकों का कैशलेस इलाज

प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक सहित अन्य कर्मी और उनके आश्रित सरकारी के साथ–साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले करीब 11.95 लाख से अधिक शिक्षक, शिक्षा कर्मी और उनके आश्रित परिवार लाभान्वित होंगे। कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ–साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इस योजना पर सरकार द्वारा प्रति कर्मी लगभग 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक व्यय किया जाएगा। यह योजना शिक्षा कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार के उद्देश्य से 'पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना की घोषणा की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 1722 विद्यालय आच्छादित हैं। पीएम श्री के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप चरणबद्ध रूप से इन विद्यालयों में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकी व डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जा रहा है। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, लैंग्वेज लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जा रहे हैं। सोलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, ऊर्जा कुशल संसाधन, पोषण वाटिका, वेस्ट मैनेजमेंट, जल संरक्षण आदि के माध्यम से इन्हें ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

नगर क्षेत्र में पहली बार शिक्षक भर्ती

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नगर क्षेत्र (संवर्ग) में पहली बार 11,508 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। पहले नगर और ग्रामीण क्षेत्र एक साथ चलते थे। 1981 में बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली प्रभावी हुई। इसके साथ ही 1983 में नगर क्षेत्र (संवर्ग) का गठन किया गया था। नगर क्षेत्र का गठन होने के बाद अब तक यहां के विद्यालयों के लिए सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं था। ग्रामीण संवर्ग में ही भर्ती की जाती थी। ग्रामीण संवर्ग से नगर संवर्ग में शिक्षकों को तबादले का अवसर दिया जाता था। किंतु नगर संवर्ग में जाने से वरिष्ठता प्रभावित होने के कारण शिक्षक अपने मूल ग्रामीण संवर्ग में रहने को प्राथमिकता देते थे। इस कारण से नगर संवर्ग के स्कूलों में काफी संख्या में अध्यापक पद खाली हो रहे थे। यहां पठन पाठन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। 11508 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी।

हर वर्ग को शिक्षा

श्रमिकों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के सभी

मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। यह विद्यालय आधुनिक सुविधाओं, हॉस्टल, भोजन, यूनिफॉर्म और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था के साथ संचालित किए जाते हैं। यहां कक्षा 6 से 12 तक पूर्णतः निःशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, चिकित्सा आदि की सुविधा दी जा रही है। आधुनिक स्मार्ट क्लास एवं खेल सुविधाओं से अटल विद्यालय सम्पन्न हैं। प्रत्येक विद्यालय में 1000 बच्चों की आवासीय क्षमता है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर व साइंस लैब जैसी अनेक सुविधाएं यहां विद्यार्थियों को प्राप्त है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सीबीएसई पैटर्न पर पाठ्यक्रम इन विद्यालयों के लिए रखा गया है। प्रत्येक विद्यालय 12 से 15 एकड़ में निर्मित किया गया है।

इसके साथ ही प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए प्रदेश में 150 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय की स्थापना की जा रही है। वहीं सभी 75 जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास किया जा रहा है। यहां प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक की शिक्षा मिल सकेगी। बालिका शिक्षा के लिए प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसे कक्षा 12 तक उच्चीकृत किया गया है। इन स्कूलों में 88,000 के करीब छात्राएं नामांकित हैं। इन छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 1.85 लाख बच्चों का निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश करवाया गया है।

पढ़ाई संग पोषण

सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के साथ–साथ बच्चों के पोषण का भी खास रूप से ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना द्वारा लगभग 1.42 लाख राजकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.46 करोड़ से अधिक बच्चों को गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 3.53 लाख से अधिक रसोइयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन पूर्ण शुद्धता को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। योगी

सरकार द्वारा रसोइयों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त ₹1000 अतिरिक्त मानदेय उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, परिधान मद में ₹500 प्रति रसोइया की सहायता भी दी जा रही है। भोजन की नियमित मॉनिटरिंग के साथ–साथ रसोइयों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। पीएम पोषण योजना का प्रभाव है कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है और उपस्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों ही उद्देश्य को एक साथ पूरा कर रही है। ♦

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
मो. : 9415003826

सबको शिक्षा, सबको छात्रवृत्ति

–डॉ. सोनाली शुभम

शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव है। जब किसी प्रतिभाशाली छात्र को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, तो यह केवल उस छात्र का नहीं बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है। यही वास्तविकता उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय बनी और वर्ष 2008 में उसने एक ऐसी योजना शुरू की, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को नई उम्मीद दे सके।

वास्तविकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने "उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली" की शुरुआत की, जिसे सामान्यतः उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसी भी छात्र की शिक्षा पैसों की कमी के कारण न रुके और हर वर्ग को पढ़ाई का समान अवसर मिले। समय के साथ इस योजना में कई सुधार और डिजिटल प्रसार किए गए हैं, जिससे यह और अधिक सशक्त और पारदर्शी बन चुकी है।

ताजा पहल और नई उपलब्धियाँ

वर्ष 2025 इस योजना के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार छात्रवृत्ति राशि का वितरण फरवरी–मार्च की बजाय सितंबर में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 सितंबर 2025 को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक भव्य समारोह में लगभग चार लाख छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की। उन्होंने इसे छात्रों के लिए "दीपावली का उपहार" बताया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रवृत्ति केवल वित्तीय सहयोग नहीं, बल्कि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें भविष्य के सपनों से जोड़ने का साधन है। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में सरकार का लक्ष्य 70 लाख से अधिक छात्रों तक इस योजना का लाभ पहुँचाने का है। आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2017 से अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को लगभग 9,150 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के छात्रों को लगभग 5,945 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि वितरित की जा चुकी है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सत्यापन प्रणाली लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इससे फर्जी आवेदन तुरंत पकड़े जाएंगे और केवल वास्तविक पात्र छात्रों तक ही राशि पहुँच सकेगी। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने "One Nation, One Scholarship" की परिकल्पना को भी आगे बढ़ाने की बात कही, जिससे भविष्य में पूरे देश में छात्रवृत्ति प्रणाली को एक समान स्वरूप मिल सके।

योजना का स्वरूप और संचालन

यह योजना शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का सशक्त उदाहरण है। इसके तहत पात्र छात्रों को शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शैक्षणिक व्ययों के लिए वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है। उद्देश्य स्पष्ट है–किसी भी छात्र को केवल फीस न भर पाने की वजह से शिक्षा बीच में न छोड़नी पड़े।

योजना का संचालन राज्य के विभिन्न विभागों के सहयोग से किया जाता है। समाज कल्याण विभाग : SC/ST और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग : OBC वर्ग के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग : अल्पसंख्यक छात्रों के लिएय जनजातीय विकास विभाग : अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। इन विभागों के समन्वय से अलग–अलग वर्गों की छात्रवृत्तियाँ तय की जाती हैं और उनका वितरण सुनिश्चित होता है।

उद्देश्य और वास्तविक महत्व

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है शिक्षा को सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचाना। यह योजना छात्रों को आर्थिक सुरक्षा देती है, ताकि वे फीस और परीक्षा शुल्क जैसे बोझ से मुक्त होकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

इसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर भी सुनिश्चित होता है। चाहे छात्र किसी भी जाति या वर्ग से हों, यदि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें सहायता मिलती है। इससे सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं में कमी आई है। यह योजना ग्रामीण इलाकों और विशेषकर लड़कियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। पहले कई बार परिवार बेटियों की पढ़ाई रोक देते थे, लेकिन अब छात्रवृत्ति मिलने से वे शिक्षा जारी रख पा रही हैं। इसका सीधा असर स्कूल छोड़ने की दर में कमी पर दिखा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना ने समाज में सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत किया है। आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिभा और परिश्रम करने वाले छात्रों को अब अवसर की कमी नहीं है।

पात्रता और वर्गीकरण

योजना का लाभ पाने के लिए छात्र का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ पारिवारिक आय सीमा तय की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए सीमा 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य (EWS) वर्ग के लिए सीमा 2 लाख रुपये प्रति वर्ष है। यह योजना केवल SC/ST या OBC तक सीमित नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि यह जाति आधारित नहीं बल्कि आवश्यकता आधारित मदद प्रदान करती है।

साथ ही, यह योजना किसी एक बोर्ड तक सीमित नहीं है। यूपी बोर्ड के अलावा CBSE, ICSE या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई छात्र उत्तर प्रदेश का निवासी है और राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।

वित्तीय सहायता की राशि

योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि एक समान नहीं होती, बल्कि यह छात्र की कक्षा और वर्ग पर निर्भर करती है।

प्री–मैट्रिक स्तर (कक्षा 9–10) : इस स्तर पर छात्रों को उनकी फीस और मूलभूत शैक्षणिक खर्च के अनुरूप सहायता दी जाती है।

पोस्ट–मैट्रिक स्तर (कक्षा 11–12 और स्नातक)

: यहाँ छात्रों को अपेक्षाकृत अधिक सहयोग मिलता है, क्योंकि उनके खर्चे भी अधिक होते हैं।

स्नातकोत्तर और शोध स्तर : कई बार पूरी फीस की प्रतिपूर्ति भी की जाती है, विशेषकर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में।

उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे महंगे कोर्स में पढ़ रहा है, तो उसके पाठ्यक्रम की फीस का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है। इस तरह यह योजना शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करती है।

आवेदन प्रक्रिया

योजना की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता और सुगमता दोनों सुनिश्चित हुई हैं। छात्र scholarship.up.gov.in वेबसाइट पर पंजीकरण करते हैं। इसके बाद नया आवेदन या "Renewal" विकल्प चुनते हैं। आवेदन पत्र में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारी और बैंक खाते की जानकारी भरनी होती है।

आवेदन के साथ आधार कार्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पिछली कक्षा की अंकतालिका और प्रवेश पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। आवेदन सबमिट करने के बाद इसकी प्रिंट कॉपी संबंधित संस्थान में जमा करनी होती है।

छात्र अपने पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि से पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदन किस चरण में है–अग्रसारित, सत्यापनाधीन, स्वीकृत या धनराशि वितरित।

चुनौतियाँ और सुधार की दिशा

योजना प्रभावी है, पर चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। आवेदन के दौरान पोर्टल का धीमा पड़ जाना, संस्थानों द्वारा समय पर आवेदन अग्रसारित न करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव प्रमुख समस्याएँ हैं।

सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। समय पर वितरण, AI आधारित सत्यापन, जागरूकता अभियान और डिजिटल सुविधा केंद्र इसकी दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हैं। भविष्य में मोबाइल हेल्पलाइन, जिला स्तर पर सहायता केंद्र और और भी सरल पोर्टल इंटरफेस योजना को और प्रभावी बना सकते हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। यह लाखों छात्रों और परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समय से पहले वितरण और तकनीकी पारदर्शिता जैसे कदम इस योजना की व्यापकता और दूरगामी महत्व को और बढ़ाते हैं।

आज जब भारत आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना जैसे प्रयास इस सपने को साकार करने की बुनियाद रख रहे हैं। यह योजना केवल धनराशि का हस्तांतरण नहीं, बल्कि छात्रों के सपनों और समाज की प्रगति में निवेश है। ◆

(लेखिका दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा से पीएच.डी. एवं शिक्षाविद् हैं)

मो. : 7517573835

अटूट प्रयास, सर्वोत्तम आपूर्ति

—डॉ. सुयश नारायण मिश्रा

लखनऊ। यह वही उत्तर प्रदेश है, जहां कुछ साल पहले तक जून, गांव और बिजली, ये तीनों शब्द एक साथ राहत का एहसास नहीं कराते थे। जून की तपती दोपहर का मतलब था बार–बार बिजली गुल होना, बंद पड़े पंखे, ठप ट्यूबवेल, अंधेरे में डूबे घर और मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते बच्चे। गर्मी का मौसम आते ही गांवों में बिजली कटौती सबसे बड़ी परेशानी बन जाती थी। खेतों की सिंचाई प्रभावित होती थी, छोटे कारोबार ठहर जाते थे और लोगों का रोजमर्रा का जीवन बिजली की अनिश्चितता पर निर्भर रहता था। लेकिन आज यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। भीषण गर्मी के बीच भी गांवों में लगातार बिजली पहुंच रही है और लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पीक डिमांड (सर्वाधिक मांग) पूरी करने के मामले में प्रदेश ने महाराष्ट्र जैसे राज्य को भी पीछे छोड़ दिया। 24 मई को उत्तर प्रदेश ने 31,824 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक डिमांड पूरी की, जबकि इसी अवधि में महाराष्ट्र में 29,463 मेगावाट की अधिकतम मांग पूरी की गई। यह उपलब्धि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी राज्य द्वारा अब तक की गई सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति का रिकॉर्ड है।

वर्ष 2026 की गर्मियां एक अलग कहानी कह रही हैं। इस बार गर्मी का तापमान भले ही 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका हो, पर बिजली व्यवस्था ने लोगों को राहत का अहसास कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह व्यापक सुधार किए हैं, उनका असर आज शहरों से लेकर गांवों तक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैनपुरी से फिरोजाबाद, एटा से अलीगढ़, बाराबंकी से सीतापुर और लखनऊ से मेरठ तक अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 24 घंटे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। गांवों के पंखे लगातार चल रहे हैं, ?खेतों में ट्यूबवेल बिना रुकावट सिंचाई कर रहे हैं, छोटे उद्योगों की मशीनें सुचारु रूप से संचालित हैं और विद्यार्थियों की पढ़ाई अब बिजली कटौती की मोहताज नहीं रही। 23 जून की रात 10 बजकर 26 मिनट पर जब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने 32,405 मेगावाट बिजली की रिकॉर्ड आपूर्ति कर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में

भी नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये रिकॉर्ड एक दिन के प्रयास से नहीं बल्कि लंबे परिश्रम का परिणाम है। इसमें ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार करने, वितरण प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने और प्रत्येक उपभोक्ता तक बेहतर बिजली पहुंचाने की निरंतर कोशिश शामिल रही है। यदि वर्ष 2017 से पहले की तस्वीर पर नजर डालें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का निर्धारित समय लगभग 11 घंटे हुआ करता था, जबकि वास्तविक आपूर्ति कई स्थानों पर केवल 8 से 11 घंटे तक ही सीमित रहती थी। अघोषित कटौती सामान्य बात थी और निर्बाध बिजली केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सिमटकर रह जाती थी। आज वही प्रदेश इस स्थिति में पहुंच चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित 18 घंटे के रोस्टर से भी अधिक, कई स्थानों पर 20 से 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों में दर्ज सुधार नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक बदलाव की कहानी है। आज बिजली केवल घरों को रोशन करने का माध्यम नहीं रह गई है। यह किसानों की सिंचाई, ग्रामीण उद्योगों की उत्पादन क्षमता, विद्यार्थियों की शिक्षा, अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और गांवों की बदलती जीवनशैली की सबसे मजबूत आधारशिला बन चुकी है। विश्वसनीय बिजली आपूर्ति ने विकास की उस श्रृंखला को गति दी है, जिसके केंद्र में गांव और गांव का आम नागरिक है। उत्तर प्रदेश की यह नई तस्वीर बताती है कि जब दूरदृष्टि, मजबूत नेतृत्व और प्रभावी क्रियान्वयन एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के जीवन का अनुभव बन जाता है। भीषण गर्मी के बीच भी रोशनी से जगमगाते गांव इस बात के साक्षी हैं कि सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के प्रयासों से 'उत्तम प्रयास, सर्वोत्तम आपूर्ति' सुनिश्चित हो सकी है।

यूपी ने बनाया नया रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पीक डिमांड (सर्वाधिक मांग) पूरी करने के मामले में प्रदेश ने महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को भी पीछे छोड़ दिया। 24 मई को उत्तर प्रदेश ने 31,824 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक डिमांड पूरी की, जबकि इसी अवधि में महाराष्ट्र में 29,463 मेगावाट की अधिकतम मांग पूरी की गई। यह उपलब्धि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी राज्य द्वारा अब तक की गई सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति का रिकॉर्ड है। इससे पहले वर्ष 2025 में 11 जून की रात 12:45 बजे 31,486 मेगावाट की पीक डिमांड प्रदेश का सर्वोच्च स्तर था। यह उपलब्धि मजबूत ऊर्जा प्रबंधन और बेहतर विद्युत वितरण व्यवस्था का परिणाम है। योगी सरकार का लक्ष्य हर घर, हर गांव और हर शहर तक निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है। इसी दिशा में लगातार प्रयास करते हुए कई क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर से अधिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। रिकॉर्ड पीक डिमांड के बाद भी प्रदेश में बिजली आपूर्ति का स्तर लगातार ऊंचा बना रहा। 24/25 मई की रात 1 बजे 29,933 मेगावाट, रात 3 बजे 30,569

मेगावाट, 25 मई की सुबह 5 बजे 29,573 मेगावाट, सुबह 10 बजे 27,392 मेगावाट तथा दोपहर 2 बजे 29,816 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। इससे स्पष्ट है कि ऊर्जा विभाग लगातार बढ़ती मांग के अनुरूप निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में सफल रहा। यूपीपीसीएल के अफसरों की मानें तो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की निगरानी में शहरी क्षेत्रों, महानगरों, तहसील मुख्यालयों, नगर पंचायतों, मंडल मुख्यालयों और औद्योगिक क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में भी अल्पकालिक कटौती दर्ज की गई, जिससे प्रदेश की बेहतर बिजली प्रबंधन व्यवस्था का पता चलता है। यूपीपीसीएल के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, शाहजहांपुर, सीतापुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़ और भदोही जैसे अनेक जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई गई। कई स्थानों पर लगातार तीन दिनों तक पूर्ण 24 घंटे बिजली आपूर्ति दर्ज की गई। इन आंकड़ों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक बिजली उपलब्ध होना पहले असाधारण माना जाता था। अब यह व्यवस्था सामान्य होती दिखाई दे रही है।

खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और कृषि की सफलता काफी हद तक ऊर्जा पर निर्भर करती है। सिंचाई पंप, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां और छोटे ग्रामीण उद्योग सभी बिजली पर आधारित हैं। नियमित बिजली मिलने से किसान निर्धारित समय पर सिंचाई कर पा रहे हैं। डीजल पंपों पर निर्भरता कम होने से लागत घट रही है। वहीं दूध उत्पादन, आटा चक्की, वेल्डिंग, फर्नीचर निर्माण, सिलाई–कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य छोटे व्यवसायों को भी निरंतर बिजली का लाभ मिल रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य को मिला लाभ

बिजली केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली मिलने से विद्यार्थियों को रात में पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाएं और इंटरनेट आधारित अध्ययन अब पहले की तुलना में अधिक सुगम हो रहे हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन संरक्षण, चिकित्सा उपकरणों का संचालन और आपातकालीन सेवाओं को भी निरंतर बिजली से मजबूती मिल रही है।

आधुनिक जीवनशैली की ओर बढ़ते गांव

आज गांवों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, इंटरनेट, स्मार्टफोन चार्जिंग, सीसीटीवी, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इन सभी सुविधाओं की आधारशिला विश्वसनीय बिजली आपूर्ति है। गांवों में छोटे दुकानदार अब डिजिटल लेन–देन कर रहे हैं। ई–गवर्नेंस सेवाएं, ऑनलाइन आवेदन, बैंकिंग और कॉमन सर्विस सेंटर भी निर्बाध बिजली के कारण अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं।

बिजलीकर्मियों की भूमिका

बिजली व्यवस्था केवल उत्पादन तक सीमित नहीं होती। उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वितरण और रखरखाव है। गर्मी के मौसम में अतिरिक्त लोड के कारण

कुमार गोयल के अनुसार बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रत्येक स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। निगम और डिस्कॉम के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। विभाग ने संभावित खराबियों को रोकने के लिए रखरखाव कार्य तेज किए हैं तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण की विशेष व्यवस्था भी की है।

ट्रांसफार्मर, फीडर और विद्युत लाइनों पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में बिजली विभाग के कर्मचारी दिन–रात फील्ड में रहकर खराबियों को दूर कर रहे हैं। ट्रांसफार्मरों की निगरानी, फीडरों का रखरखाव और शिकायतों का त्वरित समाधान बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

लगातार निगरानी पर जोर

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष

Maximum Electricity Demand Met by Top 10 States					
26.05.2025		27.05.2025		28.05.2025	
Name of State	Max Demand Met (MW)	Name of State	Max Demand Met (MW)	Name of State	Max Demand Met (MW)
Uttar Pradesh	27356	Uttar Pradesh	28691	Uttar Pradesh	28508
Gujarat	23791	Maharashtra	23608	Maharashtra	23773
Maharashtra	23137	Gujarat	22307	Gujarat	22934
Rajasthan	16046	Rajasthan	16668	Rajasthan	17220
Tamil Nadu	15382	Tamil Nadu	16290	Tamil Nadu	16047
Madhya Pradesh	12834	Madhya Pradesh	12631	Punjab	12707
Punjab	11182	Punjab	11684	Madhya Pradesh	11876
Haryana	10303	West Bengal	10582	Haryana	11044
West Bengal	10029	Haryana	10537	West Bengal	10413
Andhra Pradesh	9103	Andhra Pradesh	9061	Karnataka	9255

Source : Grid India, New Delhi

ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ती क्षमता

उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ता राज्यों में शामिल है। बढ़ती आबादी, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण के बीच ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद राज्य की वितरण प्रणाली में सुधार, बेहतर ग्रिड प्रबंधन और तकनीकी उन्नयन के कारण बिजली आपूर्ति पहले की तुलना में अधिक विश्वसनीय बनी है।

"ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी अथवा प्राकृतिक कारणों से कहीं–कहीं स्थानीय व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं।" ◆

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
मो. : 8924856004

पहले भय का परिवेश
आज पर्यटन प्रदेश
अपना यूपी बदल गया
2017 में
23.7 करोड़ पर्यटक
2025 में
156 करोड़+
पर्यटक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

उन्नत किसान, समृद्ध प्रदेश

नया भारत, नया उत्तर प्रदेश

गन्ना किसानों को ₹3.22 लाख करोड़+ का रिकॉर्ड भुगतान

गन्ना मूल्य ₹315 से बढ़ाकर ₹400 प्रति क्विंटल

विकास की गति अपार, डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश   UPGovtOfficial   CMOUttarpradesh   CMOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए विशाल सिंह, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित, सम्पादक–चन्द्र विजय वर्मा।